

निर्माणाधीन गोदाम ढहा

3 की मौत, 60 अब भी दबे, 14 का रेस्क्यू; सेना भी बचाव में जुटी

सीएम शुभेंद्रु अधिकारी ने जताया दुख

एजेंसी। कोलकाता

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के ताराताला इलाके में बुधवार को एक निर्माणाधीन गोदाम की छत ढह गई है। इस हादसे के दौरान गोदाम में कई मजदूर काम कर रहे थे। ऐसे में अभी वहां मलबे के नीचे 60 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। रिपोर्टर के मुताबिक इस हादसे में अभी तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों और राहत एंव बचाव के लिए पहुंची टीम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 11 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मौके पर भारतीय सेना भी पहुंच चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह घटना करीब दोपहर 12 बजे के करीब हुई थी। इस दौरान पास में ही पूजा भी चल रही थी। तभी जोरदार आवाज के साथ यह गोदाम ढह गया। लोगों ने बताया कि इस



निर्माणाधीन गोदाम में घटना के वक्त कंक्र्रीट ढलाई का काम चल रहा था। इसी वजह से जब हादसा हुआ, तो वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इन्हीं लोगों के ऊपर गोदाम की छत का भारी भरकम लोहा गिर पड़ा। इसे हटाने के लिए क्रेन मंगावाई गई है और बाकी हिस्सों को गैस कटर के जरिए काटकर अलग किया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई बचाव दल मौजूद हैं। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे की जानकारी सामने आते ही टीम वहां पहुंच गई थी। अभी तक मलबे के अंदर से करीब 11 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा, "ताराताला इलाके में ब्रेस पुल के

निकट ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर सुबह में इस गोदाम की छत गिर गई। हमारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इस घटना के समय कुछ लोग वहां काम कर रहे थे। हमें आशंका है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं।" अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता पुलिस, आपदा प्रबंधन समूह, नागरिक सुरक्षा और फायर एवं इमरजेंसी रिस्पॉन्स की टीम घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटी हुई है। सेना के अधिकारी भी बचाव कार्य में मदद करते दिखे, जबकि गिर चुके लोगों के बौम को हटाने के लिए क्रेन और मशीनों को लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, फ्लिहाल तेजी के साथ राहत और बचाव का काम किया जा रहा है।

मलबे में फंसे मजदूर बोला- मेरा पैर काट लो लेकिन मुझे बचा लो

हादसे के बाद बचाव कार्य के दौरान एक युवक अंकित सिंह ने मलबे में फंसे एक मजदूर को ढूंढने में अहम भूमिका निभाई। उसने घायल मजदूर का पैर फकड़कर बचाव दल को उसकी सही जगह तक पहुंचने में मदद की, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकालने का प्रयास तेज कर दिया। मलबे में फंसा मजदूर दर्द से कराहते हुए बार-बार कह रहा था- 'मैंने अपना पैर खो दिया है, अगर जरूरत हो तो बाकी हिस्सा काटकर मुझे बाहर निकालो, बस मेरी जान बचा लो।

हेल्पलाइन नंबर जारी

मुख्यमंत्री शुभेंद्रु अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री अग्निमित्रा पॉल और कौशिक चौधरी समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070, 8697981070 और 033-22143526/22535185 जारी किए हैं।

संक्षिप्त समाचार

देश में डॉक्टरों की बहुत जरूरत; निजी मेडिकल कॉलेजों की बेतहाशा फीस को लेकर आई याचिका

नई दिल्ली। इस याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों में बहुत ज्यादा फीस होने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई यह नहीं कह सकता कि निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी संस्थानों के बराबर ही फीस लेनी चाहिए। राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों में वसूली जा रही बेतहाशा फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिका आई, जिस पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। एक मेडिकल स्टूडेंट की तरफ से दायर इस याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, और राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में बहुत ज्यादा फीस वसूलने का आरोप लगाया गया था। लेकिन इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और कहा कि 'हमें इस देश में डॉक्टरों की सख्त जरूरत है'। जस्टिस बी.वी. नागरला और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। याचिका में मेडिकल स्टूडेंट ने बताया कि राजस्थान के निजी मेडिकल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं से सालाना 18.90 लाख से लेकर 25 लाख रुपए के बीच दृश्यमान फीस वसूली जा रही है, जो कि EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय 8 लाख रुपए की सीमा से कहीं ज्यादा है।

मनोहरपुर-दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जियो की सबसे तेज डाउनलोड स्पीड, बीएसएनएल का प्रदर्शन सबसे कमजोर : ट्राई



नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने राजस्थान के मनोहरपुर से दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-148) पर मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता के स्क्वेर ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, डेटा डाउनलोड स्पीड के मामले में रिलायंस जियो सबसे आगे रही, जबकि बीएसएनएल का प्रदर्शन सबसे कमजोर पाया गया। ट्राई ने बताया कि यह ड्राइव टेस्ट 2 मई को राजस्थान लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में मनोहरपुर से दौसा के बीच 62.2 किलोमीटर लंबे मार्ग पर किया गया। परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वॉयस और डेटा सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना था। रिपोर्ट के अनुसार, औसत डेटा डाउनलोड स्पीड रिलायंस जियो के लिए 247.01 एमबीपीएस दर्ज की गई, जबकि एयरटेल की 102.80 एमबीपीएस, वोडाफोन आइडिया (वीआई) की 35.97 एमबीपीएस और बीएसएनएल की मात्र 3.99 एमबीपीएस रही। डेटा अपलोड स्पीड में एयरटेल 20.93 एमबीपीएस के साथ सबसे आगे रही। जियो की अपलोड स्पीड 19.14 एमबीपीएस, वीआई की 17.25 एमबीपीएस और बीएसएनएल की 1.88 एमबीपीएस दर्ज की गई। कवरेज गैप के मामले में बीएसएनएल का प्रदर्शन सबसे कमजोर पाया गया।

मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार! 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश

नई दिल्ली। अब वो वक़्त जल्द आने वाला है जिसका लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। मतलब भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से मॉनसून राहत दिलाने वाला है। वजह यह है कि राहत की बूँदें गिराने के लिए मॉनसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है। और देश 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, मॉनसून ने महाराष्ट्र (मुंबई सहित), तेलंगाना और ओडिशा के शेष हिस्सों को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसके साथ ही, मॉनसून के बादल छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई नए इलाकों में भी पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग का स्पष्ट पूर्वानुमान है कि अगले 2-3 दिनों में मॉनसून गुजरात, महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्सों और मध्य प्रदेश में दस्तक दे देगा।



वहीं, इसके ठीक 3-4 दिन बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बाकी हिस्सों में इमझाम बारिश शुरू होने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो गई हैं। हालांकि, मौसम का मिजाज अभी डबल फेस दिखा रहा है एक तरफ जहां पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में इस पूरे हफ्ते भारी से बहुत भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4-5 दिन और दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश व विदर्भ में अगले 2-3 दिन लू का सितम अभी भी झेलना पड़ेगा।

तेजस एमके 1ए की मारक क्षमता चीन के जे-10सी जेट पर भारी

नई दिल्ली। पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा चीन के हथियारों पर निर्भर करता है, जहां उसकी 85प्रतिशत रक्षा आवश्यकताएं चीनी आपात से पूरी होती हैं। हालांकि, इन चीनी हथियारों की विश्वसनीयता और युद्धक क्षमता को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं, जैसा कि बीते साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा गया था, जब भारतीय हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल की गई चीनी मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम साबित हुए थे। अब, भारत के स्वदेशी चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट तेजस एमके1ए ने चीन के जे-10सी जेट, जिस पर पाकिस्तान अपनी वायुसेना की शक्ति का बड़ा आधार मानता है, को कई महत्वपूर्ण मामलों में पछाड़ दिया है। जे-10सी, जिसे बांग्लादेश जैसे देश भी खरीदने पर विचार कर रहे हैं, की तुलना में तेजस एमके1ए की हालिया रिपोर्ट ने चीनी जेट की क्षमताओं पर गंभीर खवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस एमके1ए की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका रडार क्रॉस सेक्शन (आरसीएस) है, जो दुश्मन के रडार पर किसी विमान की दृश्यता को निर्धारित करता है। तेजस एमके1ए का आरसीएस मात्र 0.5 वर्ग मीटर है, जबकि चीनी जे-10सी और जेएफ-17 जैसे फाइटर जेट्स का आरसीएस 1 से 1.5 वर्ग मीटर के बीच है।

अमेरिका-ईरान में समझौता, क्या कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई पर लगेगी लगाम?

एजेंसी। नई दिल्ली

अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार समझौता हो गया है। दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते के बाद मिडिल-ईस्ट का सबसे अहम समुद्री रास्ता हॉर्न दोबारा खुल गया है। इससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की किल्लत खत्म होने जा रही है और जल्द ही मार्केट में भारी ऑयल सरप्लस देखने को मिल सकता है। सरप्लस मतलब, डिमांड से ज्यादा सप्लाई होगी। जब सप्लाई ज्यादा होती है तो तेल की कीमतें कम होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अपनी जरूरत का 85 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाने वाले भारत में क्या अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम होंगी? क्या महंगाई के मोचे पर आम आदमी को राहत मिलेगी। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले दो साल में दुनिया में तेल की

रिपोर्ट: अगले दो साल में दुनिया में तेल की सप्लाई मांग के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ेगी



सप्लाई मांग के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे 2027 तक बाजार में भारी ऑयल सरप्लस की स्थिति बन जाएगी। मिडिल-ईस्ट में तनाव की वजह से रोजाना करीब 1.4 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई रुकी हुई थी, जो अब बहाल होने जा रही है। इस स्थिति पर क्रिस्टल एनर्जी के ग्लोबल एडवाइजर क्रिस्टोफ रूहल का कहना है कि साल 2027 में वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई मांग से रोजाना 10 लाख बैरल से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में कच्चे तेल

एलन मस्क को एक दिन में 11 लाख करोड़ का झटका

वॉशिंगटन। दुनिया के सबसे धनी शख्स एलन मस्क अब खरबपति (ट्रिलियनियर) नहीं रहे हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में आई भारी गिरावट ने मस्क की संपत्ति को एक ही दिन में 118 अरब डॉलर, यानी लगभग 11 लाख करोड़ रुपये कम कर दिया है। इस गिरावट के साथ उनकी कुल नेटवर्थ 957 अरब डॉलर पर आ गई है, जो उन्हें खरबपति की श्रेणी से बाहर कर देती है। हालांकि, इतनी बड़ी राशि गंवाने के बाद भी एलन मस्क अभी भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी संपत्ति दूसरे नंबर के रईस लैरी पेज से अभी भी 660 अरब डॉलर अधिक है। यह फासला इतना बढ़ा है कि इसमें जेफ बेजोस जैसे दो और अमीर समा सकते हैं, जो मस्क की बची हुई संपत्ति के विशालकाय आकार को दर्शाता है।

एलन मस्क की इस संपत्ति में गिरावट का मुख्य कारण उनकी सबसे कीमती कंपनी स्पेसएक्स के शेयरों में लगातार हो रही बिकवाली है। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में स्पेसएक्स के शेयर लगभग 23 फीसदी तक गिर चुके हैं, जिससे कंपनी के मार्केट कैप में करीब 600 अरब डॉलर की भारी कमी आई है। स्पेसएक्स के शेयरों में इसी जबरदस्त गिरावट ने एलन मस्क से खरबपति का प्रतिष्ठित ताज छीन लिया है।

एलन मस्क की इस संपत्ति में गिरावट का मुख्य कारण उनकी सबसे कीमती कंपनी स्पेसएक्स के शेयरों में लगातार हो रही बिकवाली है। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में स्पेसएक्स के शेयर लगभग 23 फीसदी तक गिर चुके हैं, जिससे कंपनी के मार्केट कैप में करीब 600 अरब डॉलर की भारी कमी आई है। स्पेसएक्स के शेयरों में इसी जबरदस्त गिरावट ने एलन मस्क से खरबपति का प्रतिष्ठित ताज छीन लिया है।

नशा मुक्त भारत के रोडमैप पर मंथन, अमित शाह 26 जून को एनसीओआरडी की शीर्षस्तरीय बैठक की करेंगे अध्यक्षता

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार, 26 जून को यहां विज्ञान भवन में नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की 10वीं शीर्षस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा आयोजित इस बैठक में देश को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि बैठक में अमित शाह 'मादक पदार्थ नियंत्रण पर विजन डॉक्यूमेंट (2026-2029)' तथा एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट-2025 जारी

करेंगे। व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया यह विजन दस्तावेज मादक पदार्थों की मांग में कमी, आपूर्ति पर नियंत्रण तथा नशे से होने वाली हानि को कम करने के लिए अगले तीन वर्षों का साझा रोडमैप प्रस्तुत करेगा। दस्तावेज में संश्लिष्ट ड्रग्स, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, युवाओं को नशे से दूर रखने, उपचार एवं पुनर्वास केंद्रों के विस्तार तथा



विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह दस्तावेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नशा मुक्त भारत' के संकल्प को साकार करने के लिए मार्गदर्शक ढांचे का कार्य करेगा। गृहमंत्री इस अवसर पर ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट कैपेन का भी शुभारंभ करेंगे। इस विशेष अभियान के तहत देशभर में विभिन्न केंद्रीय

एवं राज्य एजेंसियों द्वारा लगभग 2,09,500 किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया जाएगा, जिनका अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। इसके अलावा अमित शाह जम्मू और गुवाहाटी में नव-निर्मित एनसीबी जौनल कार्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। बैठक में 44 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्यों की सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। बैठक में आगामी तीन वर्षों के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

आपकी दुआएं, प्यार, संदेश और अटूट समर्थन हर कदम पर मेरे साथ रहा

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। संगीत के दुनिया में अप्रमोदगदग देने के लिए सिंगर अलका यागनिक को पद्म भूषण से नवाजा गया। पद्म भूषण लेने के बाद सिंगर अलका ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने फैनस को अपनी हेल्थ के बारे में बताया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को अलका यागनिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म भूषण सम्मान लेने पहुंचीं। 60 साल की यागिका अलका को एक शख्स की मदद से मंच पर चढ़ते देखा गया। उनका वीडियो जैसे ही फैनस की नजरों के सामने आया सब



उन्हें लेकर चिंतित हो गए। अब उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी दी है। अलका का कहना है कि वह पिछले दो साल से स्पॉन्डिलाइट से दूर हैं, क्योंकि हेल्थ संबंधी परेशानियों से जूझ रही हैं। उन्होंने लिखा कि सार्वजनिक मौजूदगीयों और अपनी यात्रा साझा करने से दूर रही हूं। आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं कटिन स्वास्थ्य दौर से गुजर रही थी

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल हुआ बांग्लादेश

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) में बांग्लादेश भी सदस्य के रूप में शामिल हो गया। बुधवार को आईबीसीए ने बांग्लादेश को नए सदस्य देश के रूप में स्वागत किया। एक्स अकाउंट पर अपने संदेश में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस ने बांग्लादेश की सरकार का अपने नवीनतम सदस्य देश के रूप में हार्दिक स्वागत किया। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि बिग कैट प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का और मजबूत बनाएगी। आईबीसीए ने कहा कि बांग्लादेश के इस गठबंधन में शामिल होने से वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को नई गति मिलेगी। यह कदम भविष्य की पीढ़ियों के लिए बाघों सहित अन्य प्रजातियों और उनके आवासों को सुरक्षित रखने की साझा प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस ने विश्वास व्यक्त किया कि सदस्य देशों के बीच बढ़ता सहयोग बिग कैट संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।



ज्वलंत मुद्दा संपादकीय लापरवाही की लपटों में जलती जिंदगी: कब जागेगा तंत्र?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक व्यावसायिक भवन में लगी भीषण आग ने केवल एक इमारत को नहीं जलाया, बल्कि शासन-प्रशासन की संवेदनहीनता, नियामक संस्थाओं की निष्क्रियता और व्यवस्था की खोखली पड़ चुकी जवाबदेही को भी उजागर कर दिया है। इस दुर्घटना में कोचिंग सेंटर के अनेक विद्यार्थियों की असामयिक मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि उस सड़ी-गली व्यवस्था का परिणाम है, जो हर त्रासदी के बाद कुछ दिनों तक सक्रिय दिखती है और फिर गहरी नींद में सो जाती है।

राजकोट के गेमिंग जोन में आग, दिल्ली के शिशु अस्पताल में नवजातों की मौत, दिल्ली के होटल अग्निकांड, मुजफ्फरपुर अस्पताल की दुर्घटना और अब लखनऊ का अग्निकांड-इन घटनाओं की श्रृंखला बताती है कि भारत में मानव जीवन का मूल्य लगातार घटता जा रहा है। हर बार वही बयान सुनाई देता है- 'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा', 'जांच के आदेश दे दिए गए हैं', 'कड़ी कार्रवाई होगी'। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जांच और मुआवजा ही शासन का अंतिम दायित्व है? क्या सरकारें केवल दुर्घटना के बाद शोक व्यक्त करने और मुआवजा बांटने के लिए हैं? इन जहरीली काली आग ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। कितनी ही आंखों की रोशनी छीन ली और एक काल्पित पोत दी कानून और व्यवस्था के कर्णधारों के मुंह पर।

लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी, वहां कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। यह अत्यंत गंभीर प्रश्न है कि क्या उस भवन को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त था? क्या भवन निर्माण मानकों का पालन किया गया था? क्या वहां आपातकालीन निकास मार्ग उपलब्ध थे? यदि थे, तो वे उपयोग में क्यों नहीं आए? और यदि नहीं थे, तो इतने लंबे समय तक प्रशासन की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? यह केवल भवन स्वामी की लापरवाही नहीं है। यदि कोई व्यावसायिक संस्थान नियमों की अनदेखी करते हुए वर्षों तक संचालित होता रहता है, तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र की मौन सहमति या भ्रष्ट गठजोड़ सक्रिय है। आखिर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? क्या उनका कार्य केवल लाइसेंस जारी करना और औपचारिक निरीक्षण करना भर रह गया है? या कमियां को ढंकते हुए अपनी जैब गर्म करते रहना है? वास्तविकता यह है कि देश के अधिकांश शहरों में सार्वजनिक सुरक्षा भगवान भरोसे है। ऊंची-ऊंची इमारतें खड़ी हो रही हैं, लेकिन उनमें सुरक्षा मानकों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। बहुमंजिला भवनों में अक्सर एक ही प्रवेश एवं निकास मार्ग होता है।

सैयद जकी हैदर | सम्पादक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL.SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM



संक्षिप्त समाचार

मुंद्रा ड्रास मामले में ईडी की दिल्ली में छापेमारी, नाइट क्लबों में निवेश की जांच

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 3,000 किलोग्राम मादक पदार्थ की खेप से जुड़े धनशोधन मामले में बुधवार सुबह दिल्ली में पांच स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दीन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की गई।ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। जांच में सामने आया है कि मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन का निवेश दिल्ली के नाइट क्लबों में किया गया था। इसी संबंध में ईडी वित्तीय लेनदेन और निवेश के स्रोतों की जांच कर रही है।जांच एजेंसी के अनुसार, हरप्रीत सिंह तलवार को इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पहले गिरफ्तार कर चुकी है। वह हाल ही में जमानत पर रिहा हुआ है। उल्लेखनीय है कि मुंद्रा बंदरगाह पर 2021 में लगभग 3,000 किलोग्राम हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की गई थी, जिसे देश के सबसे बड़े मादक पदार्थ तस्करी मामलों में से एक माना जाता है। मामले की जांच विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

भाजपा ने मल्लिकार्जुन खरगे पर कर्नाटक में 19 एकड़ सरकारी जमीन हड़पने का लगाया आरोप

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर निशाना साधते हुए उन पर कर्नाटक में 19 एकड़ सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि खरगे और उनके बेटे एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटक में जमीन की लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस ट्रस्ट का नाम है सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में खरगे, बेटे प्रियांक खरगे, दामाद और उनकी पत्नी शामिल हैं। ये ट्रस्ट खरगे के परिवार का है। भंडारी ने कहा, “गुलबर्गा जिले में 19 एकड़ जमीन का आवंटन भी विवादास्पद है। 19 एकड़ सार्वजनिक भूमि कांग्रेस सरकार ने खरगे के निजी ट्रस्ट को दे दी। इसका मतलब है कि 19 एकड़ सार्वजनिक जमीन एक ऐसे निजी ट्रस्ट के नियंत्रण में चली गई, जिसके सदस्यों में खरगे के परिवार के लोग शामिल हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि खरगे और प्रियांक खरगे ने इस ट्रस्ट के माध्यम से अलग-अलग जमीन पर कब्जा किया और अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए गरीबों की जमीन हड़प ली। उन्होंने कहा कि भूमि लूट का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2024 में कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड ने इस ट्रस्ट को पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी। उस समय भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस अध्यक्ष थे और आज भी हैं, जबकि प्रियांक खरगे मंत्री थे। प्रदीप भंडारी ने कहा कि जमीन का घोषित उद्देश्य एगरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट था। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजार में इस पांच एकड़ जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपये है, लेकिन जिस उद्देश्य से जमीन दी गई थी, उस दिशा में कोई गतिविधि नहीं हुई।उन्होंने सवाल उठाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसे ट्रस्ट को जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे खुद ट्रस्टी हैं, सौ करोड़ की इंडस्ट्रियल जमीन क्यों दी? भंडारी ने पूछा कि क्या खरगे और प्रियांक खरगे ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल जमीन पर कब्जा किया? ट्रस्ट उन ऐसी कौन सा काम किया, जो एगरोस्पेस और डिफेंस रिसर्च जमीन आपके प्राइवेट ट्रस्ट को दे दी गई?

दिल्ली भाजपा ने की भगवंत मान के इस्तीफे की मांग

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा एवं यमुनापर विकास बोर्ड के चेयरमैन अरविंदर सिंह लवली ने बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पहले सिख मर्यादाओं की बेअदबी करने और फिर सिख संगत एवं देश को गुमराह करने के लिए पैसे देकर नकली रिपोर्ट बनाने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भगवंत मान के पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की है।हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि कुछ माह पूर्व एक वीडियो सामने आया जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान सिख मर्यादाओं की बेअदबी करते नजर आये। इसकी शिकायत सिखों की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब ने दो सरकारी लैब से उक्त वीडियो की जांच करवाई और उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान को ही दोषी पाया गया। कुछ दिन पहले श्री अकाल तख्त साहिब के सिंह साहिबानों द्वारा यह फरमान सुनाया गया है कि भगवंत मान से कोई सिख किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा।हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि इसके बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने श्री अकाल तख्त साहिब के आरोपों को नकारा और लैब की वीडियो नकली है और उसमें भगवंत मान नहीं हैं। पंजाब सरकार भी निजी लैब की जांच रिपोर्ट सामने रखती है और दशांती है कि सरदार भगवंत मान वीडियो में नहीं हैं।दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोलवार रात कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसके बाद हरियाणा पुलिस के एफआईआर दर्ज की और उसके बाद लैब मालिक ने खुद खुलासा किया है कि रिपोर्ट पंजाब पुलिस के दो अधिकारियों ने उन पर दबाव डाल कर एवं दस लाख रुपये का लालच देकर बनवाई। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जब भगवंत मान की वीडियो की श्री अकाल तख्त साहिब ने सरकारी लैब से जांच करवाई तो फिर पंजाब सरकार ने निजी लैब से जांच क्यों करवाई। भगवंत मान ने सिख मर्यादाओं की बेअदबी की और देश का पंजाबी समाज भगवंत मान का पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा चाहता है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि गुरुओं के अंदर विश्वास रखने वालों की भावनाओं पर आघात करने वाला है। अकाल तख्त के सामने बड़े-बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी तक पेश हुए हैं। आज उसी को चैलेंज करने का प्रयास भगवंत मान एवं आम आदमी पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि आज सीधे तौर पर भगवंत मान को इस्तीफा देना चाहिए और वे सभी लोग जो मुख्यमंत्री का साथ दे रहे थे उन्हें भी सिख कोष से माफ़ी मांगनी चाहिए।

देश में एक जुलाई से वीवी-जी राम जी अधिनियम होगा लागू

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्र सरकार आगामी 01 जुलाई 2026 से विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम- 2025 यानी (वीबी-जी राम जी अधिनियम) लागू करने जा रही है। यह अधिनियम हर वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इसके तहत गांवों के विकास के लिए अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम किया जाएगा, ताकि विकास कार्य तेजी से और बेहतर तरीके से पूरे हो सकें। इसी तैयारी के तहत बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रहित कंसल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 18 मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।सरकार की योजना है कि हर गांव अपनी जरूरतों के अनुसार विकास योजना तैयार करें। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के धन और संसाधनों को जोड़कर उन कामों को पूरा किया जाएगा। इसे “एक योजना, कई स्रोतों से फंड” मॉडल कहा गया है।नई व्यवस्था के तहत ग्राम सभाएं और पंचायतें विकास की प्राथमिकताएं तय करेंगी। इनमें पानी की उपलब्धता, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और आजीविका बढ़ाने के काम तथा बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के उपाय शामिल होंगे।ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने ऐसे 318 प्रकार के कार्यों की सूची तैयार की है, जिन पर इस योजना के तहत काम किया जा सकेगा। इनमें जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, समुदायिक भवन, रोजगार से जुड़े संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य शामिल हैं।इस नई व्यवस्था से सरकारी योजनाओं में तालमेल बढ़ेगा, पैसे का बेहतर उपयोग होगा और गांवों में विकास कार्यों को ज्यादा गति मिलेगी। साथ ही पंचायतों की भूमिका भी पहले से अधिक मजबूत होगी। उल्लेखनीय है कि वीबी- जी राम जी अधिनियम-2025 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह पर लाया गया है। इस नए अधिनियम को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2025 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। एक जुलाई से यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होने के साथ ग्रामीण विकास के लिए एक नए मॉडल की शुरुआत करेगी।

भगवंत मान ने सिखों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया: भाजपा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विवादित वीडियो मामले में गुरुग्राम में एफआईआर दर्ज होने पर उन पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा कि मान ने कथित धन का उपयोग करके एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई और सिख समुदाय की भावनाओं को चुनौती देने का प्रयास किया।भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के पांच सिंह साहिबान द्वारा आदेश जारी किया गया कि

मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क हादसा, छह घायल, दो की हालत गंभीर

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर और पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार छह युवक-युवतियां घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि देर रात दुर्घटना की सूचना मिलने पर जांच अधिकारी और पुलिस टीम तुरंत प्रेस एम्बुलेंस रोड स्थित मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। मौके पर एक क्षतिग्रस्त स्विफ्ट कार मिली, जो सड़क किनारे पेड़ और डिवाइडर से टकराई हुई थी। पुलिस ने क्राइम टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाा और साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान पता चला कि दुर्घटना मंगलवार की रात करीब 11:40 बजे हुई थी। हादसे में घायल सौ नू कर्नोजिया

दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के कार्य का शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और बिजली मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो के सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के कार्य की बुधवार को शुरुआत की। इसके मौके पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव और डीएमआरसी के चेयरमैन के. श्रीनिवास भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली के शहरी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। यह कॉरिडोर कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों और लैंडमार्क तक आसान कनेक्टिविटी देगा, जिससे रोजाना हजारों कर्मचारियों, नागरिकों और आने-जाने वालों के लिए पहुंच आसान हो जाएगी। प्रमुख मेट्रो लाइनों के साथ बेहतर इंटीग्रेशन से

कैंसर के खिलाफ 18 महीने तक जारी रहे लंबे संघर्ष के बाद आस्ट्रेलियाई मरीज स्पेशलाइज्ड रोबोटिक रेक्टल कैंसर सर्जरी करवाने के लिए भारत आए

» फोर्टिस मानेसर के डॉक्टरों ने पेट में चीरा या अस्थायी स्टोमा लगाए बिना ही सफलतापूर्वक ट्यूमर निकाला

लोकतंत्र की शान

दिल्ली/एनसीआर:

कोलोरेक्टल कैंसर केयर में हाल के वर्षों में हुई प्रगति का परिचय देते हुए, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में 45-वर्षीय आस्ट्रेलियाई मरीज की, जो कि प्रारंभिक चरण के रेक्टल कैंसर से ग्रस्त थे, एव्वांस रोबोटिक ट्रांसएनल मिनीमेली इन्वेसिव सर्जरी (टीएमआईएस) की है। यह पारंपरिक बड़ी सर्जरी की तुलना में चुनौती मरीजों के लिए स्पेशलाइज्ड सर्जरी है जिससे अंगों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। इस प्रक्रिया को डॉ विनय सैमुअल गायकवाड़, सीनियर

बुलाकर सफाई देने का मौका दिया। तब भगवंत मान ने कहा कि यह वीडियो एआई जेनरेटेड है, लेकिन जब वीडियो की फोरेंसिक जांच करवाई गई तो स्पष्ट हो गया कि वीडियो पूरी तरह असली है। उन्होंने कहा कि इसके बाद अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरुद्वीही और खालसा पंथ का विरोधी करार देते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और दुनियाभर के सिखों को आदेश दिया कि कोई भी सिख मान से कोई नाता नहीं रखेगा। सिरसा ने आरोप लगाया कि भगवंत मान के करीबी सहयोगी स्वप्न शर्मा ने गुरुग्राम के एक होटल में फोरेंसिक प्रयोगशाला से संबंधित एक बैठक की थी। इस बैठक के दौरान पैसेा का लेन-देन हुआ और वीडियो को इस तरह से

शारदा हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत दाग रहित मिड-फेशियल ट्यूमर सर्जरी कर 22 वर्षीय युवती को दी नई जिंदगी

लोकतंत्र की शान

ग्रेटर नोएडा: शारदा हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 22 वर्षीय सुश्री प्रीति कुमारी का मुफ्त इलाज हुआ, जिसमें शारदा हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने उनके चेहरे से एक बहुत बड़ा और बिना कैंसर वाला ट्यूमर को दुर्लभ और दाग-रहित सर्जरी के माध्यम से सफलतापूर्वक निकाल दिया। इस मुश्किल प्रक्रिया से न सिर्फ ट्यूमर पूरी तरह निकल गया, बल्कि मरीज के चेहरे का लुक, देखने वाली बनावट और मुंह के काम करने का तरीका सुरक्षित रहा और चेहरे पर कोई निशान नहीं पड़ा। मरीज लगभग 12 साल से चेहरे पर लगातार बढ़ती सूजन के साथ जी रही थी। समय बीतने के साथ ट्यूमर ने आंख के संकेत और नाक के आस-पास के ज़रूरी हिस्सों को काफी हद तक हटा दिया था, जिससे

सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों में रियायती फीस की मांग खारिज की

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की जस्टिस बीवी नागरला की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उस याचिका को खारिज दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा था कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को ये लाभ नहीं कर सकते हैं।याचिका राजस्थान के एक ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र हर्षवर्धन सिंह ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरला ने कहा कि निजी कॉलेजों से सरकारी कॉलेजों की तरह फीस में रियायत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। निजी कॉलेजों को अपना वित्तपोषण खुद करना होता है। सरकारी कॉलेजों को सरकार रियायत देती है और यही बड़ा फर्क है। जस्टिस नागरला ने टीएमए पई के फैसले का



जिफ़ करते हुए कहा कि कैपिटेशन फीस पर रोक लगाई गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज की सामान्य फीस नहीं लगेगी। याचिकाकर्ता का कहना था कि ईडब्ल्यूएस की आय सीमा सालाना आठ लाख तक की है। आठ लाख की आय वाला ईडब्ल्यूएस का छात्र निजी मेडिकल कॉलेज की फीस कैसे भर सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थान में निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस 18.9 लाख से 25 लाख के बीच है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र निजी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएगा। तब कोर्ट ने कहा कि आप स्कॉलरशिप या सबवेंशन लीजिए।



चेहरे की बनावट खराब हो गई और काम करने में दिक्कतें बढ़ गई थीं। आयुष्मान भारत योजना के जरिए अत्याधुनिक इलाज मिलने से मरीज

को बिना किसी पैसे के बोज़ के ख़ास सर्जिकल देखभाल मिल सकी। 2006 में स्थापित शारदा हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा, NCR में एक

दिगंबर जैन संतों और मयूर पिच्छी पर टिप्पणी को लेकर मेनका गांधी को आपत्ती पत्र



लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन के निदेशक श्री मनोज कुमार जैन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी को एक औपचारिक पत्र भेजकर दिगंबर जैन संतों द्वारा उपयोग की जाने वाली मयूर पिच्छी के संबंध में उनके हालिया कथनों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। फाउंडेशन द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उक्त बयान से देशा्पर के जैन समाज, विशेषकर दिगंबर जैन संत समुदाय तथा भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं ठाढ़ हुई हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि

दिगंबर जैन संतों द्वारा उपयोग की जाने

वाली मयूर पिच्छी केवल प्राकृतिक

रूप से झड़े हुए मोरपंखों से बनाई

जाती है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म जीवों

की रक्षा करना तथा जैन धर्म के मूल

सिद्धांत ‘अहिंसा’ का पालन करना है।

फाउंडेशन ने यह भी उल्लेख किया

कि मोरपंख न केवल जैन परंपरा में,

बल्कि सनातन संस्कृति में भी अत्यंत

पवित्र और श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान

श्रीकृष्ण के मुकुट में सुशोभित मोरपंख

भारतीय आस्था और सांस्कृतिक

विरासत का महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे

में बिना पर्याप्त प्रमाण के लगाए गए

आरोप समाज में भ्रम उत्पन्न करने

के साथ-साथ धार्मिक भावनाओं को

आहत कर सकते हैं।

उपराज्यपाल ने अपराध पर सख्त नियंत्रण रखने का दिया निर्देश

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और कामकाज व कल्याण से जुड़ी मुख्य प्राथमिकताओं की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस बल को अपराध पर सख्त नियंत्रण रखने का निर्देश देते हुए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।अधिकारियों को लगातार कोशल बढ़ाने, पुलिसिंग के बेहतरीन तरीके अपनाने, एआई और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल करने और कम्युनिटी पुलिसिंग व जानकारी जुटाने में आरडब्ल्यू और मार्केट एंसेसिएशन को सक्रिय रूप से शामिल करने का निर्देश दिया। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा



की।उपराज्यपाल ने ट्रैफिक नियमों को सख्त से लागू करके ट्रैफिक की चुनौतियों से निपटने की जरूरत पर जोर दिया, खासकर गलत दिशा में गाड़ी चलाने और ज्यादा जाम वाली जगहों पर साथ ही सड़क का इस्तेमाल करने वालों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने पुलिसकर्मियों के कल्याण, बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और पुलिस रिहायशी

परिसरों को ‘जोरो-वेस्ट’ कॉलोनिनों में बदलने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि सशक्तिकरण के साथ-साथ जवाबदेही और सार्थक परिणाम भी होने चाहिए। पूरे पुलिस बल को अपना पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया, क्योंकि ये नए संकल्प के साथ काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली का हर निवासी ज्यादा सुरक्षित और बेहतर सेवा का अनुभव कर सके।



संक्षिप्त समाचार

भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने की अपील, सोशल मीडिया पर निगरानी तेज

लोकतंत्र की शान , सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता, सहरसा: जिला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और शक्ति एवं सौहार्द बनाए रखें। यह अपील 22 जून 2026 को हनुमान चौक स्थित अखाड़ा स्थल से जुड़े एक मामले को लेकर फैली अफवाहों के मद्देनजर जारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व से बांस में बंधे एक झंडे को दूसरे स्थान पर स्थापित किए जाने की सूचना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं फैलने लगी थीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष, अंचल पदाधिकारी कहरा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच व सत्यापन किया। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित झंडे को वास्तव में एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाया गया था, जिसे बाद में स्थानीय लोगों द्वारा पुनः उसी स्थान पर स्थापित कर दिया गया। इस संबंध में सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर विधिस्मत्त कार्यवाई की जा रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक तत्व इस मामले को लेकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें।

बिजली खंभे पर काम कर रहे कर्मों को मौत, हाजीपुर में 35 फीट ऊंचाई से गिरा

लोकतंत्र की शान , हाजीपुर। हाजीपुर में बिजली के खंभे पर काम कर रहे एक मानव बल को करंट लग गया। इस हादसे में राजेश कुमार यादव नामक कर्मी 35 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना तीन फेज लाइन जोड़ने के दौरान हुई। राजेश कुमार यादव बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहे थे, तभी अचानक लाइन में करंट प्रवाहित हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्विच बोर्ड संचालित करने में हुई लापरवाही के कारण बिजली आपूर्ति चालू कर दी गई, जिससे यह हादसा हुआ। करंट लगने से राजेश कुमार यादव बुरी तरह झुलस गए और उन्हें गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद घायल कर्मी को हाजीपुर के गणपति अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना को लेकर विभागीय लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं और मामले की जांच तथा जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाई की मांग की जा रही है।

बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता शिविर, 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के तहत 'शिक्षा और अधिकारों' पर जोर

लोकतंत्र की शान , हाजीपुर। वैशाली को बाल विवाह की कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त बनाने के उद्देश्य से हाजीपुर प्रखंड के समाचक हरीली गांव स्थित महादलित टोले में एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 'बाल विवाह मुक्त भारत अभियान' के तहत आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य हाजीपुर प्रखंड सहित पूरे वैशाली जिले को बाल विवाह से पूरी तरह मुक्त बनाना है। कार्यक्रम का आयोजन स्थायी कन्हौड़ शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान और उत्तर राष्ट्रस फॉर चिड्डेन (JRC) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इसकी अध्यक्षता वार्ड सदस्य राजीव पासवान ने की, जबकि संचालन अधिकार मित्र संतोष कुमार ने किया। इस दौरान संस्थान के सचिव और जेआरसी के निदेशक डॉ. सुधीर कुमार शर्मा ने बाल विवाह को एक गंभीर सामाजिक बुराई और कानूनी दंडनीय अपराध बताया। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का हवाला देते हुए कहा कि बाल विवाह कराने, उसमें शामिल होने या बढ़ावा देने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। डॉ. शुक्ला ने जोर देकर कहा कि बाल विवाह को रोकना समाज के उज्ज्वल भविष्य के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि संस्थान इस कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने हेतु कानूनी, सामाजिक और जमीनी स्तर पर निरंतर प्रयास कर रहा है। अधिकार मित्र संतोष कुमार ने उपस्थित ग्रामीणों से संवाद करते हुए बाल विवाह के दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है, जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है और उनके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूरे भविष्य को अधकार में डाल देता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक हर बच्चा शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा, तब तक इस कुप्रथा को पूरी तरह खत्म कर पाना संभव नहीं है। संतोष कुमार ने कहा कि शिक्षा, जन जागरूकता और सभी के सामूहिक प्रयास से ही इस कुरीति को समाप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित वार्ड सदस्य राजीव पासवान ने अभियान की सराहना की और बाल विवाह के खिलाफ चल रही इस मुहिम में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी पंचायत को बाल विवाह मुक्त बनाने का सार्वजनिक संकल्प भी लिया।

फिलपकार्ट वेयरहाउस पर मजदूरों का हंगामा, वेतन वृद्धि और मिस-पंच को लेकर एनएच-22 जाम

लोकतंत्र की शान , हाजीपुर। वैशाली के धोबघट्टी स्थित फिलपकार्ट वेयरहाउस में बुधवार सुबह मजदूरों ने वेतन वृद्धि और मिस-पंच के मुद्दों को लेकर हंगामा किया। लगभग एक हजार महिला और पुरुष प्रखंडियों ने कंपनी के गेट पर धरना-प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 22 (NH-22) को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कंपनी के गेट पर ही डेरा डाल दिया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद काफी मशक्कत से वे बातचीत के लिए तैयार हुए। इससे पहले भी वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन किया गया था। फिलहाल, वैशाली पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और कंपनी के गेट पर पुलिस बल तैनात है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी नाइट शिफ्ट की सैलरी 18,000 रुपये से घटाकर 13,000 रुपये कर दी गई है। कंपनी ने उनकी पोस्ट भी कम कर दी है। पहले नाइट शिफ्ट के लिए अलग से 120 रुपये मिलते थे, जिसे अब 50 रुपये कम कर दिया गया है। श्रमिकों का कहना है कि कंपनी जिस तरह से काम लेती है, उस हिस्सा से उन्हें भुगतान नहीं किया जाता है। साथ ही, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिलती। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे दूसरे जिलों और राज्यों से आकर यहां कांपर पर रहते हैं। उन्हें प्रति श्रमिक 738 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उतना भुगतान नहीं किया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

बागमती का जलस्तर बढ़ा, मुजफ्फरपुर में पीपापुल क्षतिग्रस्त, 22 पंचायतों का संपर्क टूटने का था खतरा

लोकतंत्र की शान , मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से औड़ाई और कटरा प्रखंडों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सबसे गंभीर स्थिति कटरा प्रखंड में देखने को मिली, जहां क्षेत्र की लाइफलाइन माने जाने वाले पीपापुल पर संकट गहरा गया। बागमती के तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में बहकर आई जलकुंभी पुल में फंस गई, जिससे पुल पर अत्यधिक दबाव बन गया और उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ समय के लिए लोगों में पुल के बह जाने की आशंका को लेकर दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीपापुल कटरा और आसपास के दर्जनों गांवों के लिए जीवनरेखा है। यदि यह पुल बह जाता तो 16 से 22 पंचायतों के लाखों लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट जाता। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 30 से 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती। ग्रामीणों के अनुसार रोजाना चार हजार से दस हजार लोग इस पुल का उपयोग करते हैं। छात्र, किसान, मरीज, व्यवसायी और नौकरीपेशा लोग इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। स्थानीय निवासी मुकेश सिंह ने बताया कि दशकों से यह पीपापुल इलाके के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपर्क साधन बना हुआ है। पुल के कारण लोगों का प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से सीधा संपर्क बना रहता है। वहीं सुपन कुमार सिंह ने कहा कि इस पुल के बिना क्षेत्र के लोगों की जिंदगी काफी कठिन हो जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी अधिकांश जरूरतें इसी मार्ग के जरिए पूरी होती हैं। इसलिए इस पुल की सुरक्षा और स्थायी समाधान बेहद जरूरी है।

बी0टेक पाट्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2022-26) के परीक्षा परिणामों की डिजिटल माध्यम से समयबद्ध घोषणा की गई

लोकतंत्र की शान , राजीव रंजन की रिपोर्ट / पटना

बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना द्वारा आज दिनांक 24 जून, 2026 को बी०टेक पाट्यक्रम (शैक्षणिक सत्र 2022-26) के परीक्षा परिणामों की डिजिटल माध्यम से समयबद्ध घोषणा की गई। इस अवसर पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की माननीया मंत्री श्रीमती शीला कुमारी ने अपने कर कमलों द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किया। यह पहल विश्वविद्यालय की पारदर्शी, आधुनिक एवं छात्र केंद्रित परीक्षा प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कार्यक्रम में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, श्री हिमांशु शर्मा, भा०प्र०से०, निदेशक-सह-अपर सचिव श्री अहमद महमूद भा०प्र०से०, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति प्रो० डॉ० एस० के० वर्मा तथा कुलसचिव डॉ० प्रदीप कुमार की गरिमामयी



उपस्थिति रही। अपने संबोधन में माननीया मंत्री श्रीमती शीला कुमारी ने कहा कि डिजिटल माध्यम से परीक्षा परिणामों की समयबद्ध घोषणा राज्य में तकनीकी शिक्षा

को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं तकनीक संचालित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे विद्यार्थियों को समय पर परिणाम उपलब्ध होंगे तथा उच्च शिक्षा एवं

विकसित भारत मिशन के तहत दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम शुरू, रोजगार सृजन पर जोर



लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता, सहरसा: विकास भवन में बुधवार को "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना, बिहार-2026" के अंतर्गत दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार, अपर समाहर्ता श्री निशांत एवं निदेशक (NEP)

द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा योजना के उद्देश्यों, उसके प्रभावी क्रियाव्यवsn, रोजगार सृजन तथा ग्रामीण आजीविका के संवर्धन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्मुखीकरण कार्यक्रम में कोशी प्रमंडल के अंतर्गत

आने वाले जिलों—सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल—से कुल 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को योजना के प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं उनके दायित्वों के प्रति प्रशिक्षित और जागरूक करना है। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से योजना का प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण क्रिानव्यवsn सुनिश्चित होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित होंगे।

प्राइड सेलिब्रेशन से आगे बढ़कर, ‘समाज’ ने उपचार स्मृतियों और अपनत्व की कहानियों को दिया मंच

लोकतंत्र की शान/ मोहम्मद शबीब आलम

कोलकाता : कोलकाता ने एक ऐसी शाम का अनुभव किया, जो भावनात्मक अभिव्यक्ति, आत्ममंथन और सशक्त कहानी-कथन से भरपूर थी। प्रांतकथा द्वारा प्रस्तुत 'समाज' एक विशेष प्राइड मंथ डांस-थिएटर प्रस्तुति थी, जिसने कवीर समुदाय के जीवानुभवों के माध्यम से स्मृति, क्षति, संघर्ष, दुद्रुता और उपचार जैसे विषयों को मंच पर जीवंत किया। कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी (केसीसी) में आयोजित इस प्रस्तुति ने व्यक्तिगत अनुभवों को पहचान, स्वीकृति और अपनत्व पर आधारित एक भावनात्मक कलात्मक संवाद में परिवर्तित कर दिया। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें बर्नार्ड लिंग, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट-जनरल, कोलकाता डॉ. संतोष गिरी, निदेशक, कोलकाता रिश्ता प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुश्री



सुदेशना राय फूड कंसल्टेंट, समीक्षक एवं एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ता सुश्री रुक्माना कपाडिया तथा अम्मोलाइट आईडिएटर्स की सह-संस्थापक एवं एलजीबीटीक्यू कार्यकर्ता सुश्री सुनेहा साहा शामिल थीं। उनकी उपस्थिति ने समावेशिता, समझ और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने वाले मंचों की बढ़ती आवश्यकता और महत्व को रेखांकित किया। इस पहल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुल ने एलजीबीटीक्यूआइए+ युवाओं के बीच सार्थक संवाद और सहभागिता को बढ़ावा देने में प्रांतकथा की भूमिका की सराहना की। उन्होंने

संस्था को एक सुरक्षित और समावेशी मंच उपलब्ध कराने के लिए बधाई दी, जहाँ कोलकाता और मुंबई के युवा कला, कहानी-कथन और साझा अनुभवों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ सके। कॉन्सुलेट ने यह देखकर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि विविध आवाजें संवाद में शामिल हुईं, अपनी पहचान का उत्सव मनाया और समाज में अधिक दृश्यता तथा समावेशन को प्रोत्साहित किया। साथ ही, प्रांतकथा को एक प्रभावशाली प्राइड मंथ आयोजन के लिए बधाई दी, जिसने सहानुभूति, समझ और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा दिया।

सिर्फ एक मंचीय प्रस्तुति से कहीं अधिक, 'समाज' एक अंतरंग और गहराई से भावनात्मक अनुभव के रूप में सामने आया, जिसने नृत्य, कहानी-कथन और वास्तविक जीवन के अनुभवों को एक साथ पिरोते हुए कवीर जीवन के विभिन्न आयामों को उजागर किया। प्राइड मंथ के अवसर पर प्रस्तुत इस कार्यक्रम ने केवल दृश्यता और उत्सव तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि स्मृतियों, क्षति, दिल टूटने, संघर्ष, उपचार और अपनत्व की खोज जैसे विषयों पर भी विचार किया। प्रभावशाली प्रस्तुतियों और ईमानदार कथाओं के माध्यम से इसने दर्शकों को उन भावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया, जो एक और अत्यंत व्यक्तिगत थीं, तो दूसरी और सार्वभौमिक रूप से परिचित थीं। इस प्रकार, 'समाज' ने सहानुभूति, आत्मचिंतन और सार्थक संवाद के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया, जिसने स्वीकृति, समझ और मानवीय जुड़ाव के महत्व को रेखांकित किया।

कोलकाता में बड़ा हादसा! निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरी, मलबे में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका तीन लोगों की मौत

लोकतंत्र की शाा/ मोहम्मद शबीब आलम

कोलकाता : कोलकाता के तारातला इलाके से बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई. यहां एक निर्माणाधीन गोदाम की छत अचानक गिर गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे के समय कई मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हुए थे.छत गिरते ही आसपास चौख-पुकार मच गई और लोगों ने तुरंत राहत एजेंसियों को सूचना दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि कुछ मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. यह दुर्घटना तारातला थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्रेस ब्रिज के पास ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर हुई. यहां एक बड़े गोदाम का निर्माण कार्य चल रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे अचानक इमारत की छत का एक हिस्सा भूभ्रंसारक नीचे गिर पड़ा. उस समय मजदूर रोज की तरह अपने काम में लगे हुए थे. छत गिरने के बाद भारी मलबा चारों तरफ फैल गया. कुछ मजदूर समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि अन्य के फंसे होने की आशंका के चलते तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया. घटना की जानकारी मिलते ही कोलकाता पुलिस, आपदा प्रबंधन समूह (DMG), सिविल डिफेंस और दमकल



विभाग की टीमों मौके पर पहुंच गई. सभी एजेंसियां मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. अधिकारियों ने बताया कि अब तक चार लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है. हालांकि, यह आशंका बनी हुई है कि अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हो सकते हैं. इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रखा गया है.

मुहर्रम के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित



लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता, सहरसा: आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं बेहतर व्यवस्थाओं के साथ संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय स्थित परिसदन में एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने संयुक्त रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जो एक और अत्यंत व्यक्तिगत थीं, तो दूसरी और सार्वभौमिक रूप से परिचित थीं। इस प्रकार, 'समाज' ने सहानुभूति, आत्मचिंतन और सार्थक संवाद के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया, जिसने स्वीकृति, समझ और मानवीय जुड़ाव के महत्व को रेखांकित किया।

पर विशेष निगरानी, जुलूस मार्गों की समीक्षा, यातायात प्रबंधन तथा आपसी भाईचारा एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि हर स्तर पर सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, ताकि अध्यक्षता जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने संयुक्त रूप से जोड़ने का प्रयास किया, जो एक और अत्यंत व्यक्तिगत थीं, तो दूसरी और सार्वभौमिक रूप से परिचित थीं। इस प्रकार, 'समाज' ने सहानुभूति, आत्मचिंतन और सार्थक संवाद के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया, जिसने स्वीकृति, समझ और मानवीय जुड़ाव के महत्व को रेखांकित किया।

प्रतिबंधित उमानाथ घाट पर हजारों श्रद्धालुओं का स्नान, बैरिकेडिंग तोड़ बच्चे तेज धार में नहाते दिखे

लोकतंत्र की शान, पटना

भैरव एकादशी के अवसर पर पटना जिले के बाढ़ स्थित प्रसिद्ध उमानाथ गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रतिबंधित घोषित घाटों तक पहुंच गए, जिससे स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। लगभग एक माह पहले इसी घाट पर हुए नाव हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने उमानाथ के तीन प्रमुख घाटों में से दो को खतरनाक घोषित कर वहां आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी।

बैरिकेडिंग और चेतावनी के बावजूद घाटों पर पहुंची भीड़: हादसे के बाद प्रशासन की ओर से घाटों पर लाल कपड़े और



बैरिकेडिंग लगाई गई थी। शुरुआती दिनों में निगरानी के लिए चौकीदारों की तैनाती और लाउडस्पीकर से चेतावनी भी दी जा रही थी। लेकिन भैरव एकादशी के धार्मिक महत्व को देखते हुए सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पहुंचने

लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई लोगों ने बैरिकेडिंग पार कर प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्नान किया। **बच्चे तेज धारा में दिखे, मौके पर नहीं दिखी निगरानी:** स्थिति उस समय और चिंताजनक हो गई जब कुछ बच्चे नदी की तेज

धारा के बीच तैरते नजर आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस समय घाट पर निगरानी के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल या कर्मी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा, प्रतिबंध के बावजूद छोटी नावों के परिचालन की भी सूचना सामने आई, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। **निर्जला एकादशी से पहले व्यवस्था की मांग:** घटना के बाद उमानाथ मंदिर में जुड़े लोगों और स्थानीय नागरिकों ने आगामी निर्जला एकादशी के दौरान संधावित भीड़ को देखते हुए घाटों पर बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है कि प्रतिबंध लागू होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग घाट तक कैसे पहुंचे और निगरानी व्यवस्था क्यों प्रभावी नहीं दिखी।

संक्षिप्त

समाचार

नेपाल में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में उछाल, 11 महीनों में 10,845 वाहन आयात

काठमांडू। चालू वित्तीय वर्ष के पहले 11 महीनों में नेपाल ने 25.55 अरब रुपये मूल्य के 10,845 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आयात किए हैं। इनमें विभिन्न मॉडल और क्षमता वाले वाहन हैं, जिनकी क्षमता 50 किलोवाट से लेकर 200 किलोवाट से अधिक तक है। यह नेपाल में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। कस्टम विभाग के आंकड़ों के अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान 50 किलोवाट तक क्षमता वाले 3,680 इलेक्ट्रिक वाहन आयात किए गए। इन वाहनों का कुल मूल्य लगभग 5.65 अरब रुपये रहा। इसी तरह, 51 किलोवाट से 100 किलोवाट क्षमता वाले 6,357 इलेक्ट्रिक वाहन इसी अवधि में नेपाल पहुंचे, जिनकी कुल आयात लागत 16.49 अरब रुपये रही। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 51–100 किलोवाट श्रेणी के वाहन आयात संख्या और कुल मूल्य—दोनों ही मामलों में नेपाल के EV बाजार पर सबसे अधिक हावी रहे। नेपाल में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात में लगातार हो रही वृद्धि के पीछे उपभोक्ताओं की बढ़ती रुचि, सरकार की सहयोगी नीतियां और देशभर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

नेपाल में पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की गिरफ्तारी को यूएमएल ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध और गैरकानूनी

काठमांडू। सीपीएन यूएमएल ने पार्टी के उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए इसे राजनीतिक प्रेतार, प्रतिशोधपूर्ण और गैरकानूनी करार दिया है। पुर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सोमवार को सुर्खेत जिले से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आगे की जांच के लिए उन्हें सात दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति भी दे दी है। बुधवार को आयोजित पार्टी सचिवालय की नौवाँ बैठक में उनकी बिना शर्त और तत्काल रिहाई की मांग की गई। बैठक में देशभर के पार्टी सदस्यों और समर्थकों से राज्य तंत्र के कथित अधिनायकवादी, प्रतिशोधात्मक और भेदभावपूर्ण इस्तेमाल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिरोध और जन-जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान भी किया गया। बैठक के बाद जारी बयान में यूएमएल ने कहा कि वह इस गिरफ्तारी को राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चुनौती देगा। पार्टी का आरोप है कि गिरफ्तारी बिना किसी ठोस तथ्य या प्रमाण के की गई और इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक प्रतिशोध लेना है। पार्टी ने विशेष अदालत के उस निर्णय पर भी असहमति जताई, जिसमें जांच अवधि के दौरान पौडेल को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई। पार्टी का कहना है कि यह आदेश न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं और न्याय के पक्ष में खड़े आम नागरिकों से भी देशव्यापी अभियान में शामिल होने की अपील की गई। पार्टी का कहना है कि यह अभियान राज्य एजेंसियों के किए जा रहे मनमाने और भेदभावपूर्ण कदमों के विरोध में चलना चाहिए।

राहुल ने उठाया मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी का मामला
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी के मामले पर बुधवार को रोष प्रकट किया है। राहुल का कहना है कि यह कोई आम आपराधिक घटना नहीं है - यह एक भराशाही हुई अर्थव्यवस्था का घटना है। उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी की एक मलबा समाने आगी है। यहां नौकरी का झूठा वादा कर 13 मजदूरों को पिछले दो साल से बंधक बनाकर रखा गया था। उन्हें लाठियों, बेटों से पीटा जाता था। साथ ही वहां रातबीरान कुत्ते से उन पर हमला करवाया गया। एक मजदूर के बंधन से निकल भागने बाद पुलिस को मामले का पता चला और बाकी मजदूरों को छुड़वाया गया। राहुल गांधी ने इस घटना पर आज कहा कि मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा, “बिना मजदूरी दिए काम करवाने के अलावा, मजदूरों को कुत्तो से कटवाया गया, भाले से गोदा गया, कोड़े मारे गए और उन्हें भेरेशियों का चारा खिलाया गया। यह इंसानी गरिमा पर हमला है - पीड़ितों को न्याय के साथ पुनर्वास और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी समझना जरूरी है कि मजदूर ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में किन महत्वूरियों में फंस जाते हैं?” कांग्रेस नेता ने इसका दोष राज्य और केन्द्र सरकार पर मढ़ते हुए कहा कि “जब रोखगार खत्म हो जाते हैं, आमदनी उठर जाती है, और सबसे कमजोर वर्गों के लिए भत्ते मंरगेया और श्रम कानूनों जैसी सुरक्षाएं कमजोर कर दी जाती हैं, तो हताशा बढ़ती जाती है।” उन्होंने कहा कि लोग विकल्प या सुरक्षा के अभाव में ऐसे शोषण का आसान शिकार बन जाते हैं।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने लद्दाख के उपराज्यपाल से की मुलाकात

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने लद्दाख अध्ययन दौरे के दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उनके साथ दिल्ली विधानसभा के सदस्य सूर्य प्रकाश खत्री, संजय गोयल एवं अहीर दीपक चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक ने शासन, विकास, सतत प्रगति और क्षेत्र के समक्ष उपस्थित पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक विचार-विमर्श का अवसर प्रदान किया। यह जानकारी एक बयान में दी गयी। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद वहां हो रहे व्यापक विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लद्दाख में जिलों की संख्या दो से बढ़ाकर सात कर दी गई है, जिससे प्रशासनिक पहुंच मजबूत हुई है तथा विकास कार्यों में तेजी आई है। उपराज्यपाल ने क्षेत्र में चल रही महत्वपूर्ण अवसरचानात्मक परियोजनाओं, विशेषकर रणनीतिक सुरंगों एवं संपर्क-सुविधाओं के निर्माण कार्यों का भी उल्लेख किया, जो वर्षभर निबांध आवागमन सुनिश्चित करने, आर्थिक विकास को गति देने तथा स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका स्यांगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को दिल्ली विधानसभा द्वारा डिजिटल प्रशासन और पर्यावरणीय सततता के क्षेत्र में किए गए विभिन्न नवीन पहलों से अवगत कराया। उन्होंने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के सफल क्रिया-व्यय का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके माध्यम से कागज के उपयोग में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे बड़ी संख्या में युक्तों के संरक्षण में सहायता मिली है तथा विधानसभा की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई है। गुप्ता ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली विधानसभा परिसर में स्थापित 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र से विद्युत खपत में उल्लेखनीय बचत हुई है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा क्षमता में अतिरिक्त 300 किलोवाट की वृद्धि की योजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर विधानसभा अपनी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति में लगभग आत्मनिर्भर हो जाएगी।

कतर गैस प्लांट विस्फोट में सूरत के सनी पटेल की मौत की पुष्टि
सूरत। कतर के रस लफ्फान स्थित गैस प्लांट में हुए धीषण विस्फोट में सूरत के दुमस क्षेत्र के मोटो मोहल्ला निवासी सनी पटेल की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। हादसे के बाद से उनके सुरक्षित लौटने की उम्मीद लगाए बैठे परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सनी पटेल के भाई रवि पटेल ने कतर में उनके पार्थिव शरीर की पहचान कर ली है। भारतीय दूतावास की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंपा जाएगा। सनी का पार्थिव शरीर बुधवार को कतर से अहमदाबाद लाया जाएगा, जहां से उसे सूरत पहुंचाया जाएगा। परिजनों ने बताया कि सनी पटेल अपनी द्यूट्री पर जाने और लौटने के दौरान पत्नी को फोन करना कभी नहीं भूलते थे। हादसे वाली रात भी उन्होंने नाइट शिफ्ट पर जाने से पहले पत्नी से बातचीत कर बताया था कि वे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद उनका कॉल संपर्क नहीं हो पाया। उनकी पत्नी उस अंतिम बातचीत को याद कर बार-बार भावुक हो रही हैं। बताया जाता है कि पिता और बड़े भाई के निधन के बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संधालने के लिए सनी और उनके भाई कतर गए थे। सनी वहां एक औद्योगिक कंपनी में मैकेनिकल फिटर के रूप में कार्यरत थे। परिवार में अधिकांश सदस्य महिलाएं हैं और इस दुखद घटना से पूरा परिवार गहरे शोक में डूब गया है।

पांच त्यक्ति लापता, भूस्खलन से पांच जिलों का सड़क संपर्क कटा

अरुणाचल बाढ़

एजेंसी, इटानगर

अरुणाचल प्रदेश के केयी पान्योर जिले में पोसा में नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निपको) प्रोजेक्ट के कॉलोनी के आस-पास के इलाकों में बीती रात से बुधवार सुबह तक लगातार हुई भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गयी। क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अरुणाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ के संबंध में दी गयी जानकारी के अनुसार आज दोपहर 3 बजे तक अचानक आई बाढ़ के चलते पांच लोग लापता हैं। निपको प्रोजेक्ट हेड के अनुसार पांच लोगों के लापता होने की सूचना है। इस बीच कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को एम्बुलेंस से चोरो ले जाया गया है। पितापुल में सड़क बंद होने के कारण तीनों घायलों को एम्बुलेंस से आगे ले जाने से पहले, सड़क के बंद हिस्से को पैदल चलकर पार किया गया। कई जगहों पर जबरनस्त भूस्खलन के कारण केयी पैन्योर जिले के पोसा, होज और पोटिन इलाकों



मे भूस्खलन के कारण लगभग पांच अन्य जिला भी पूरी तरह कट गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, 23 और 24 जून की रात हुई लगातार बारिश से अचानक बाढ़ आ गई और यज्ञाली सर्कल के तहत निपको प्रोजेक्ट कॉलोनी और उसके पास निचले इलाकों में पानी भर गया। इससे कॉलोनी के लगभग 20 क्वार्टर क्षतिग्रस्त हो गए और एक निर्माणाधीन रिटेंगिंग वॉल बह गई। चार पहिया वाहनों सहित कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। केयी पान्योर की जिला उपायुक्त श्वेता नागरकोटी मेहता के अनुसार, भूस्खलन के कारण प्रभावित यज्ञाली और होज-पोटिन, दोनों तरफ से प्रभावित हुए हैं। सड़क बंद होने के करण प्रभावित क्षेत्र में पहुंचना मुश्किल हो गया है। पोटिन और पोसा के बीच फंसा एक भू-वैज्ञानिक (जियोलाॅजिस्ट) बचाव का इंतजार कर रहा है। जिला प्रशासन ने बताया कि शुरू में

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टु को पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने सुनाई धार्मिक सजा पंजाब में चार धार्मिक स्थानों पर माथा टेककर लेंगे आशीर्वाद

एजेंसी, चंडीगढ़

पुलिस कर्मचारियों पर आपत्तिजक टिप्पणी करने के मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टु को चार धार्मिक स्थानों पर माथा टेकने की धार्मिक सजा सुनाई है। रवनीत बिट्टु बुधवार को अपने वकीलों के साथ अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गद्दी के समक्ष पेश हुए और अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मेरे शब्द 100 फीसदी कानूनी तौर पर गलत थे, जिसके लिए मैंने माफी भी मांगी।

बिट्टु ने कहा कि उन्हें सबसे पहले सैगरूर में एक एसपी रैंक के अधिकारी ने रोका था। उस अधिकारी ने बताया कि ओएसडी ऑंकार को बलिया थाने में हिरासत में रखा गया है। इसके बाद वह बलिया थाने पहुंचे, जहां उन्हें फिर बताया गया



कि ऑंकार को संगरूर ले जाया गया है। इसके बाद वह धुरी पहुंचे, जहां एक एसएचओ रैंक के अधिकारी ने उनकी गाड़ी के सामने वाहन लगाकर रास्ता रोक दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान उनके साथ बदमाजी की गई और कुछ ऐसे शब्द कहे गए, जिनसे वह आहत हुए। बिट्टु ने कहा कि उस समय हालात तनावपूर्ण थे और पुलिस के व्यवहार से वह भावुक हो गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि उनकी ओर से भी कोई आपत्तिजनक शब्द निकले हों, तो इसके लिए वह मीडिया के सामने पहले ही माफी मांग चुके हैं।

रिम्स में मेडिकल सीट अलॉटमेंट अनियमितता की जांच तेज, सीआईडी टीम ने खंगाले दस्तावेज

एजेंसी, रांची

राजधानी रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में मेडिकल अलॉटमेंट और नामांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच अब तेज हो गई है। मामले की जांच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) की टीम बुधवार को रिम्स पहुंची और डीन कार्यालय समेत विभिन्न विभागों में उपलब्ध दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच शुरू की। जांच एजेंसी नामांकन प्रक्रिया और टेंडर से जुड़े मामलों में हुई संभावित गड़बड़ियों की पड़ताल कर रही है। सीआईडी अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई पिछले शैक्षणिक सत्र में हुए दाखिलों से संबंधित शिकायतों के आधार पर की जा रही है। जांच के दौरान प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड, काउंसिलिंग दस्तावेज, आवंटित सीटों का ब्यौरा तथा संबंधित प्रशासनिक फाइलों का अवलोकन किया जा रहा है। टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन किया गया था या नहीं।

पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ संबंध रखने के संदेह में कर्नाटक में एक युवक गिरफ्तार

एजेंसी, नई बेंगलुरु

कर्नाटक के दावणगेरे जिले के हरिहर तालुक के बन्निकोडु गांव से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सुहैल (20) के रुप में हुई है। उस पर पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों से संपर्क रखने का संदेह है। पुलिस और केंद्रीय खुफिया विभाग ने एक संयुक्त ऑपरेशन में युवक को गिरफ्तार किया। हरिहर ग्रामाण पुलिस थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पकड़ा गया आरोपित युवक देश में बड़े पैमाने पर विध्वंसक और समाज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा हो सकता है। पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर अयोध्या के श्रीराम मंदिर को बम विस्फोट के जरिए निशाना बनाने की बात कही। हालांकि, जांच एजेंसियां अभी इसकी सत्यता और



उसके वास्तविक इरादों की जांच कर रही हैं।

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरो ने भीड़िया से बात करते हुए बताया कि प्रार्थमिक जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वह काम की तलाश में दावणगेरे आया था। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि वह चैट के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के संपर्क में था। उसके मोबाइल फोन से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। फिलहाल आरोपित पुलिस हिरासत में है और जांच जारी है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के 21 जिलों में किसानों का विरोध प्रदर्शन

एजेंसी, चंडीगढ़

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में बुधवार को किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आया। किसान संगठनों ने पंजाब के 21 जिलों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाले। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले भी फूंके। अमृतसर में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में सैकड़ों किसान भाजपा कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि इस समझौते की जुलाई के अंत तक लागू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस संबंध में किसानों, खेत मजदूरों और



अन्य संबंधित वर्गों से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया गया।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि यदि यह ट्रेड डील लागू होती है तो पंजाब सहित पूरे देश के किसानों, खेत मजदूरों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनका कहना है कि विदेशी उत्पादों के लिए बाजार खोलने से स्थानीय कृषि और डेयरी

श्रीनगर में 8वीं मुहर्रम का जुलूस, सड़कों पर उमड़ा शोक मनाने वालों का सैलाब

एजेंसी, श्रीनगर

काले झंडों और शोक के बैनरों के साथे में बुधवार सुबह श्रीनगर के शहर के केंद्र में हजारों श्रद्धालु जमा हुए। पारंपरिक 8वीं मुहर्रम का जुलूस शुरू हुआ जिससे गुरु बाजार-डलगेट का रास्ता कबंला के शहीदों की याद में शोक मनाने वालों की भीड़ से भर गया। गुरु बाजार से डलगेट तक सड़कों पर गमगीन माहौल था। रास्ते में सबील, मेडिकल कैप और वॉलंटियर्स द्वारा चलाए जा रहे सेवा स्टॉल लगे थे जो जुलूस में शामिल लोगों को पानी, जलपान और मदद दे रहे थे। साथ ही सड़कों पर शोक-गीत (मर्सिया) गुंज रहे थे और बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हो रहे थे।

जानकारी के अनुसार जालूस सुबह-सुबह गुरु बाजार से शुरू हुआ और पारंपरिक रास्ते से होते हुए बुदशाह कदल और एम.ए. रोड से गुजरा। इसमें शामिल लोग काले झंडे लिए हुए थे और शोक से जुड़ी रस्मों में हिस्सा ले रहे थे। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले से आए एक शोक मनाने वाले ताहिर अली ने कहा, “यह सिर्फ एक जुलूस नहीं है बल्कि याद और कुर्बानी का

सफर है। लोग इस दिन का हिस्सा बनने के लिए पूरे साल इंतजार करते हैं।”

एक और प्रतिभागी मुबाशिर हसन ने कहा कि माहौल में दुख और एकता दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, “आप यहां कश्मीर के हर कोने से आए लोगों को देख सकते हैं। वॉलंटियर्स और अधिकारियों के इंतजामों से सब कुछ आसानी से हो रहा है।”

जैसे-जैसे जुलूस शहर के केंद्र से आगे बढ़ा, स्थानीय लोग सड़कों के किनारे से इसे देखते रहे जबकि वॉलंटियर्स शोक मनाने वालों की मदद करने और रास्ते में लगे सेवा स्टॉलों को संधालने में व्यस्त रहे।

अधिकारियों ने बताया कि जुलूस के सुचारु संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे जिनमें सुरक्षा बलों की तैनाती, ड्रोन से निगरानी, मेडिकल सुविधाएं, ट्रैफिक कंट्रोल, सफाई व्यवस्था और जरूरी सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखना शामिल था।

इस रूट से जुड़ी मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहा जबकि अलग-अलग जिलों और इलाकों से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की खास व्यवस्था की गई थी।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पंजाब के 21 जिलों में किसानों का विरोध प्रदर्शन

◆ कई स्थानों पर केंद्र सरकार और ट्रंप के पुतले फूँके, किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी

नगर और तरनतारन में प्रदर्शन किए गए। कई स्थानों पर भाजपा कार्यालयों और भाजपा नेताओं के घरों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भारत-अमेरिका ट्रेड डील को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान अपने अधिकारों और कृषि क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।

पूर्ण गर्भवती महिला के सम्मान में मंच से उतरे मुख्यमंत्री विजय

एजेंसी, चेन्नई

तमिलनाडु सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 401 अन्धर्थियों को नियुक्ति आदेश वितरित करने के लिए चेन्नई में आयोजित एक समारोह उस समय भावनात्मक क्षण का साक्षी बन गया, जब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने एक पूर्ण गर्भवती महिला की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए स्वयं मंच से नीचे उतरकर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री के इस मानवीय व्यवहार ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया और पूरे सभागार में भावुक माहौल बन गया। सरकारी सेवा में चयनित 401 अन्धर्थियों में अक्षयलक्ष्मी नाम की एक महिला भी शामिल थीं, जो गर्भावस्था के अंतिम चरण में हैं। उनकी प्रसव तिथि 28 जून निर्धारित है। जीवन के महत्वपूर्ण सपनों में शामिल सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति की



परवाह किए बिना समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जब चयनित अन्धर्थियों को क्रमवार मंच पर बुलाकर नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, तब मुख्यमंत्री विजय की नजर अक्षयलक्ष्मी पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उनकी स्थिति को समझते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें मंच तक आने के लिए सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इसके बाद मुख्यमंत्री ने परंपरागत प्रोटोकॉल को एक तरफ रखते हुए स्वयं मंच से नीचे उतरने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सीधे उस स्थान तक पहुंचे जहां अक्षयलक्ष्मी बैठी हुई थीं। वहां उन्होंने उन्हें अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान अक्षयलक्ष्मी भावुक दिखाई दीं।

दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो के सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के कार्य का शुभारंभ

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और बिजली मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो के सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के कार्य की बुधवार को शुरुआत की। इसके मौके पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव और डीएमआरसी के चेयरमैन के. श्रीनिवास भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद रहे।

मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली के शहरी ट्रान्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। यह कॉरिडोर कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों और लैंडमार्क तक आसान कनेक्टिविटी देगा, जिससे रोजाना हजारों कर्मचारियों, नागरिकों और आने-जाने वालों के लिए पहुंच आसान हो जाएगी। प्रमुख मेट्रो लाइनों के साथ बेहतर इंटीग्रेशन से राजधानी में



यात्रा और भी आसान और कुशल हो जाएगी। आधुनिक और नागरिक-केंद्रित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यात्रा के कीमती समय की बचत करेगा, यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा। डीएमआरसी ने एक बयान में कहा कि यह स्टेशन मौजूदा मैजेंटा लाइन (जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम मार्ग तक) के विस्तार के तौर

पर फेज V(ए) के तहत बनाया जा रहा है। केंद्रीय सचिवालय स्टेशन एक ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा, जहां नई मैजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो लाइन और वॉयलेट लाइन से आसानी से जुड़ जाएगा। इस खास सुविधा से सरकारी कर्मचारियों और लुटियंस जॉन व आसपास के प्रशासनिक इलाकों में आने-जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा।

यह कॉरिडोर 9.913 किलोमीटर लंबा है और इसमें नई अंडरग्राउंड स्टेशन हैं- शिवाजी स्टेडियम, युगे-युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, वॉर मेमोरियल-हाई कोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम और इंड्रप्रस्था। यह प्रोजेक्ट नई दिल्ली के मुख्य इलाकों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे प्रमुख सरकारी दफ्तरों, न्यायिक संस्थानों, राष्ट्रीय स्मारकों और कन्वेंशन सुविधाओं तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, साथ ही पूरे नेटवर्क की क्षमता और यात्रियों की सुविधा भी बेहतर होगी।

मिशन बाल विवाह मुक्त भारत 2030- क्या विवाह निमंत्रण पत्रिका पर दूल्हे दुल्हन की जन्मतिथि अनिवार्य करना सामाजिक क्रांति का नया अध्याय बनेगा?-समग्र व्यापक विश्लेषण



एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत आज विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। ऐसे समय में जब देश विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब बाल विवाह जैसी सदियों पुरानी सामाजिक कुप्रथा का अस्तित्व केवल सामाजिक चिंता का विषय नहीं,बल्कि मानवाधिकार, लैंगिक समानता,शिक्षा,स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए भी गंभीर चुनौती है। संविधान द्वारा प्रदत्त समानता, स्वतंत्रता और गरिमायम्य जीवन के अधिकार के बावजूद देश के अनेक हिस्सों में बाल विवाह आज भी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से जारी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है,बल्कि ऐसे व्यावहारिक और तकनीक-संचालित उपायों की आवश्यकता है जो समाज के प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें। बाल विवाह प्रतिबंध कानून में अनेक लोगों पर अनेक जवाब दहिया निर्धारित की गई है जो मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि शापद अनेक लोगों को यह मालूम नहीं होगा इसलिए मैं बता देना चाहूंगा कि मैरिज हॉल,बैंड और कार्ड विक्रेताओं की कानूनी जिम्मेदारी (पूरे भारत में)भले ही कार्ड पर जन्मतिथि

» **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 धारा 10 और 11- प्रिंटिंग प्रेस मालिक,मैरिज हॉल संचालक,कैटरर्स,बैंड संचालक, फोटोग्राफर, पंडित, मौलवी, पादरी व अन्य सेवा प्रदाता इस कानून के तहत उत्तरदायी हैं**
» जब हर बाल विवाह सेवा प्रदाता,प्रिंटिंग प्रेस, मैरिज हॉल,कैटरर्स,बैंड संचालक, फोटोग्राफर धर्मगुरु और हर नागरिक कानून के साथ खड़ा होगा, तभी यह लक्ष्य 2030 वास्तविकता में बदल सकेगा
-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

लिखने का नियम हर राज्य में न हो, लेकिन बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत सेवा प्रदाताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान पूरे भारत में समान रूप से लागू है: यदि भारत के किसी भी राज्य में बाल विवाह (लड़की 18 से कम या लड़का 21 से कम) होता है,तो केंद्रीय कानून के तहत मैरिज हॉल संचालक, बैंड वाले, टेंट वाले, कैटरर्स और कार्ड प्रिंट करने वाले सभी को अपराध को बढ़ावा देने का दोषी माना जाता है।उम्र की पुष्टि किए बिना बाल विवाह में सेवा देने या उसे बढ़ावा देने पर देश के किसी भी कोने में 2 साल की कठोर जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसलिए, कानूनी रूप से सुरक्षित रहने के लिए पूरे भारत के सभी मैरिज हॉल और लॉन संचालकों को बुकिंग के समय दूल्हा-दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र (आधार, जन्म प्रमाण पत्र आदि) की जांच करनी ही पड़ती है,चाहे वे किसी भी राज्य में हों।किसी संदर्भ में राजस्थान द्वारा लागू तथा महाराष्ट्र द्वारा विचाराधीन वह व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसके तहत विवाह निमंत्रण पत्र पर दूल्हा-दुल्हन की जन्मतिथि अनिवार्य रूप से छापने का प्रावधान किया जा रहा है। यह कदम केवल

एक प्रशासनिक नियम नहीं, बल्कि बाल विवाह रोकने की दिशा में एक दूरदर्शी सामाजिक नवाचार के रूप में सटीकता से देखा जा सकता है। साथियों, बाल विवाह की समस्या केवल कम उम्र में विवाह तक सीमित नहीं है। यह लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है,किशोरावस्था में मातृत्व के जोखिम बढ़ाती है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को प्रभावित करती है, घरेलू हिंसा की संभावनाओं को बढ़ाती है तथा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भी बाल विवाह उम्मूलन को प्राथमिकता दी गई है। भारत ने पिछले वर्षों में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति अवश्य की है, किंतु अभी भी कई राज्यों और जिलों में बाल विवाह की घटनाएँ चिंताजनक स्तरपर बनी हुई हैं। महाराष्ट्र में बाल विवाह दर 21.9 प्रतिशत से घटकर 19.6 प्रतिशत होने का तथ्य प्रगति का संकेत है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए नए और प्रभावी उपायों की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। साथियों, विवाह निमंत्रण पत्र पर दूल्हा दुल्हन की जन्मतिथि छापने का प्रस्ताव पहली दृष्टि में साधारण प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारतीय समाज में विवाह कार्ड केवल निमंत्रण का माध्यम नहीं होता, बल्कि वह विवाह की सार्वजनिक घोषणा भी होता है।जब कार्ड पर वर-वधू की जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित होगी, तब परिवारों के लिए उम्र छिपाना कठिन हो जाएगा। रिशतेदार,पड़ोसी, समाज के लोग तथा प्रशासनिक अधिकारी भी आसानी से यह सत्यापित कर सकेंगे कि विवाह करने वाले युवक-युवती कानूनी आयु के हैं या नहीं। इस प्रकार विवाह कार्ड स्वयं एक प्रारंभिक सत्यापन दस्तावेज का स्वरूप ग्रहण कर सकता है।डिजिटल युग में यह व्यवस्था और अधिक प्रभावी सिद्ध



हो सकती है। यदि विवाह कार्ड पर जन्मतिथि के साथ क्यूआर कोड अथवा डिजिटल सत्यापन व्यवस्था जोड़ी जाए तो आयु प्रमाण की प्रक्रिया और पारदर्शी बन सकती है। भविष्य में यह प्रणाली विवाह पंजीकरण, जन्म प्रमाणपत्र और आधार आधारित सत्यापन सेcc भी जोड़ी जा सकती है। इस प्रकार तकनीक और कानून का समन्वय बाल विवाह रोकने के लिए एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। साथियों,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने केवल माता-पिता या अभिभावकों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया है, बल्कि विवाह से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को कानूनी दायरे में रखा है। यही इस कानूनी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।अधिनियम की धाराएं 10 और 11 स्पष्ट करती हैं कि जो भी व्यक्ति बाल विवाह को आयोजित करने,प्रोत्साहित करने या उसमें सहयोग करने का कार्य करेगा, वह दंड का भागीदार होगा। इस दृष्टि से प्रिंटिंग प्रेस मालिक, मैरिज हॉल संचालक,कैटरर्स, बैंड संचालक, फोटोग्राफर, पंडित, मौलवी, पादरी तथा अन्य सेवा प्रदाता केवल

व्यवसायी नहीं, बल्कि कानून के तहत उत्तरदायी हितधारक भी हैं। साथियों, प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि विवाह कार्ड छापने से पहले आयु प्रमाण पत्र की जांच अनिवार्य कर दी जाती है, तो बाल विवाह की तैयारी प्रारंभिक चरण में ही पकड़ी जा सकती है। विवाह कार्ड किसी भी विवाह प्रक्रिया का पहला औपचारिक दस्तावेज होता है। यदि इसी स्तर पर सत्यापन सुनिश्चित हो जाए, तो बाल विवाह की संभावना काफी हद तक कम की जा सकती है। साथ ही रिकॉर्ड सुरक्षित रहने की व्यवस्था जांच एजेंसियों को भी आवश्यक साध्य उपलब्ध करा सकती है। यह व्यवस्था केवल दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक दृष्टिकोण का उदाहरण है।इसी प्रकार मैरिज हॉल, लॉन, होटल और विवाह स्थलों के संचालकों पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वे किसी भी विवाह समारोह के आयोजक नहीं होते, लेकिन आयोजन के लिए आवश्यक मंच उपलब्ध कराते हैं। यदि बुकिंग के समय आयु प्रमाणपत्र स्व-घोषणा पत्र और पहचान दस्तावेजों की जांच अनिवार्य रूप से

की जाए तो अनेक संभावित बाल विवाहों को रोका जा सकता है। कानून ने उन्हें केवल सत्यापन तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि संदेह की स्थिति में पुलिस अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सूचना देना भी उनकी कानूनी जिम्मेदारी बनाया है। यह व्यवस्था नागरिक सहभागिता आधारित शासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथियों, धार्मिक नेताओं की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।भारतीय समाज में विवाह धार्मिक औरसांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।जब पंडित, मौलवी, पादरी या अन्य धार्मिक अधिकारी विवाह संपन्न कराते हैं तब समाज उन्हें नैतिक मार्गदर्शक के रूप में देखता है। इसलिए यदि धार्मिक नेतृत्व स्वयं आयु प्रमाण को अनिवार्य मान ले और नाबालिगों का विवाह कराने से स्पष्ट इनकार करें, तो सामाजिक स्तर पर बड़ा परिवर्तन संभव है। यही कारण है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में धार्मिक एवं सामुदायिक नेताओं की सक्रिय भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। साथियों, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान केवल कानून आधारित कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का राष्ट्रीय आंदोलन है। वर्ष 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। इस अभियान के अंतर्गत चलाया गया 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम इस बात का संकेत है कि सरकार केवल दंडात्मक उपायों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि समाज की सोच बदलने का भी प्रयास कर रही है। स्कूलों,कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों और सामुदायिक संगठनों को जोड़ना इसी रणनीति का हिस्सा है। साथियों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनाई गई बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली भी उल्लेखनीय है। जिला, तालुका और ग्राम स्तर पर गठित समितियाँ बाल

विवाह रोकने की दिशा में स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाती हैं। विशेष रूप से उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करना जहां बाल विवाह की दर अधिक है, एक लक्ष्य आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। गन्ना कटाई के लिए पलायन करने वाले श्रमिक परिवारों में बाल विवाह की अधिक संभावना को पहचानकर उनके बच्चों के लिए विशेष आवासीय और डे-केयर सुविधाएं विकसित करना यह दर्शाता है कि सरकार समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई केवल कानून और प्रशासन के सहारे नहीं जीती जा सकती। इसके लिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता भी० उत्तरी ही आवश्यक है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि जहां लड़कियों की शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, वहां बाल विवाह की घटनाएं स्वतः कम हो जाती हैं। इसलिए विद्यालयों में बाल अधिकारों की शिक्षा, किशोर-किशोरियों के लिए परामर्श कार्यक्रम और परिवारों के लिए जागरूकता अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।।आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक और स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। साथियों, 18 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्देशों ने बाल विवाह उम्मूलन की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि बच्चों की गरिमा, स्वायत्तता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्णकालिक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति तथा विशेष इकाइयों के गठन के निर्देश इस बात को रेखांकित करते हैं कि समस्या के समाधान के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाना आवश्यक है। यह निर्णय बाल विवाह विरोधी कानूनों के

प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत न्यायिक आधार प्रदान करता है।भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो कानून के प्रावधानों ने भी बाल विवाह के प्रति कानूनी दृष्टिकोण को और कठोर बनाया है। अब यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इसका अर्थ यह है कि बाल विवाह को केवल पारिवारिक या सांस्कृतिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह बाल संरक्षण और मानवाधिकार से जुड़ा गंभीर कानूनी प्रश्न भी है। साथियों, भारत में बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष कोई नया नहीं है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे महान समाज सुधारकों ने 19वीं शताब्दी में ही इस कुप्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। शादी अधिनियम से लेकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 तक की यात्रा यह दर्शाती है कि भारत ने समय-समय पर अपने कानूनों के अधिक प्रगतिशील बनाया है। किंतु इतिहास यह भी सिखाता है कि कानून तभी सफल होते हैं जब समाज उनका समर्थन करे।आज आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों द्वारा विकसित किए जा रहे नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने पर गंभीर विचार किया जाए। विवाह निमंत्रण पत्र पर जन्मतिथि छापने का नियम, डिजिटल सत्यापन प्रणाली, सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही, सामुदायिक निगरानी और तकनीकी रिपोर्टिंग जैसे उपाय मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हैं जो बाल विवाह उम्मूलन की दिशा में निर्णायक साबित हो।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेष्‌ज्ञ स्‌तंभकार सहित्‌यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

आपातकाल का अंत कितना भयावह : लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा



लेखक - सौरभ वाण्येय

25 जून 1975 की आधी रात का काला अध्याय कैसे कोई भूल सकता है? गर्मी, तपिश और आंधी ने तो जगन्नाथ को पहले से ही झुलसा रखा था ऊपर से रेडियो पर आया संदेश से पूरा देश सकते में आ गया। आपातकाल ने तो पढ़ा था न पहले कभी देखा था अचानक आए राजनीतिक तूफान ने देश में अफरातफरी मचा दी। देश में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादस्पद अध्याय माना जाता है। लगभग 21 महीनों तक चले इस दौर ने न केवल राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर दिया, बल्कि नागरिक स्वतंत्रताओं, अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक मूल्यों पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े किए। मार्च 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ, तब देश ने राहत की सांस तो ली, लेकिन इसके पीछे छिपी पीड़ा, भय और लोकतांत्रिक संस्थाओं को हुई क्षति लंबे समय तक महसूस की गई।आपातकाल का अंत इसलिए भी भयावह कहा जाता है क्योंकि उस समय तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता काफी कमजोर हो चुकी थी। संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर सत्ता का प्रभाव बढ़ गया था। जनता के अधिकार सीमित हो गए थे और भय का वातावरण बन गया था। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि यदि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा न हो तो शासन निरंकुशता की ओर बढ़ सकता है। आपातकाल के दौरान प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। अखबारों को, सरकारी अनुमति के बिना समाचार प्रकाशित करने की स्वतंत्रता नहीं थी। विरोधी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा गया। लोकतंत्र की आत्मा मानी जाने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई थी। आपातकाल के अंतिम चरण में सबसे अधिक

आलोचना जबरन नसबंदी अभियान और झुगुगी-झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाइयों को लेकर हुई। कई स्थानों पर प्रशासनिक दबाव में लोगों को नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। गरीब और कमजोर वर्ग इस नीति का सबसे बड़ा शिकार बने। इससे जनता में व्यापक असंतोष पैदा हुआ। अनेक परिवारों ने सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट झेले, जिसकी पीड़ा आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपातकाल का अंत इसलिए भी भयावह कहा जाता है क्योंकि उस समय तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता काफी कमजोर हो चुकी थी। संसद, न्यायपालिका और मीडिया पर सत्ता का प्रभाव बढ़ गया था। जनता के अधिकार सीमित हो गए थे और भय का वातावरण बन गया था। लोगों को यह एहसास होने लगा था कि यदि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा न हो तो शासन निरंकुशता की ओर बढ़ सकता है। हालांकि, मार्च 1977 के आम चुनावों ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को भी साबित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चुनाव कराने का निर्णय लिया और जनता ने मतदात के माध्यम से अपना फैसला सुनाया। पहली बार केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। यह लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण क्षण था।आपातकाल की समाप्ति ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों से गहरा लगाव रखती है। सत्ता चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः जनता ही सर्वोच्च होती है। इस दौर ने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। आज,आपातकाल के पांच दशक बाद भी यह घटना एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में याद की जाती है। इसका संदेश स्पष्ट है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि नागरिक अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन से मजबूत होता है। आपातकाल का अंत भयावह अनुभवों और लोकतंत्र की पुनर्जन्मिति दोनों का प्रतीक था। यह इतिहास हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए समाज को सर्वेद सजग रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जागरूक नागरिक ही होते हैं।



आलेख-विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला',स्वतंत्र पत्रकार एवं रत्नम्कार

25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की वह तिथि है,जिसे स्वतंत्र भारत के सबसे विवादस्पद और बहुचर्चित राजनीतिक निर्णयों में गिना जाता है।आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की सलाह पर देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित इस आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं,प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को कठोर परीक्षा के दौर से गुज़ारा। लगभग पाँच दशक बाद भी आपातकाल केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है,बल्कि लोकतंत्र को निरंतर सजग रखने वाली चेतावनी है।उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इन्दिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य घोषित किए जाने,जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे व्यापक जनोदोलन और राजनीतिक अस्थिरता के माहौल के बीच आपातकाल लागू किया गया। इसके बाद जो घटनाएँ सामने आईं, उन्होंने लोकतंत्र की बुनियाद को झकझोर दिया।विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियाँ हुईं,प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई,नागरिक अधिकार सीमित कर दिए गए और सत्ता का अभूतपूर्व केंद्रीकरण देखने को मिला।जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई,अटल बिहारी वाजपेयी,लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस सहित हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया।मिसा (MISA) और अन्य कानूनों के तहत व्यापक गिरफ्तारियाँ

» **1975 में जनता ने सत्ता को सबक सिखाया था,क्या आज की राजनीति इतिहास से सीख रही है? 1975 का आपातकाल, वर्तमान चुनौतियाँ और संविधान की चेतावनी इतिहास केवल स्मृति है या वर्तमान के लिए एक आईना ?**

हुई।अनेक समाचार- पत्रों को समाचार प्रकाशित करने से पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी।लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले अभिव्यक्ति के अधिकार पर पहरा बैठ गया था।सर्वोच्च न्यायालय का चर्चित एडीएम जलपुर मामला आज भी भारतीय न्यायिक इतिहास में बहस का विषय है।उस समय न्यायपालिका का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के दबाव के सामने कमजोर दिखाई दिया, जबकि न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना का असहमति वाला मत लोकतांत्रिक साहस का प्रतीक बन गया।बाद में गठित शाह आयोग ने भी प्रशासनिक और राजनीतिक दुर्упयोगों की ओर संकेत किया। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा कितनी आवश्यक है।किन्तु भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह रही कि जनता ने अंततः अपना फैसला सुनाया।1977 के आम चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी।यह केवल सरकार की हार नहीं थी,बल्कि लोकतंत्र की जीत थी।जनता ने यह संदेश दिया कि लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसी नेता,दल या सरकार के पास नहीं, बल्कि मतदाता के पास होती है। बाद के वर्षों में कांग्रेस के अनेक नेताओं ने स्वीकार किया कि आपातकाल एक गंभीर राजनीतिक भूल थी।लोकतंत्र केवल ढण्ड देने की व्यवस्था नहीं है,वह सुधार का अवसर भी देता है।यही कारण था कि 1980 में जनता ने पुनः इन्दिरा गांधी को सत्ता में लौटने का अवसर दिया।यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का अद्भुत उदाहरण था। 1975 में जनता ने सत्ता को सबक सिखाया था,क्या आज की राजनीति इतिहास से सीख रही है? 1975 का आपातकाल, वर्तमान चुनौतियाँ और संविधान की चेतावनी इतिहास केवल स्मृति है या वर्तमान के लिए एक आईना

? यही वह बिंदु है,जहाँ इतिहास वर्तमान से संवाद करता है।आज जब देश आपातकाल की वर्षगाँठ को याद करता है,तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न भी उठता है कि क्या लोकतंत्र की समीक्षा केवल अतीत तक सीमित रहनी चाहिए अथवा वर्तमान की परिस्थितियों का भी उसी कसौटी पर परीक्षण होना चाहिए?क्या आपातकाल की स्मृति केवल राजनीतिक हथियार है या लोकतांत्रिक आत्ममंथन का अवसर?प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह वर्षों में भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं।आधार भूत संरचना का विस्तार,एक्सप्रेस-वे,रेलवे और हवाई अड्डों का विकास,डिजिटल इंडिया अभियान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण,जनधन योजना,यूपीआई क्रांति,वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती उपस्थिति, जी-20 की अध्यक्षता और विदेश नीति में संतुलित दृष्टिकोण को व्यापक रूप से सराहा गया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की संतुलित कूटनीति,वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उसकी भूमिका तथा अमेरिका, रूस,यूरोप और पश्चिम एशिया के साथ समानांतर संबंधों ने भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। यह उपलब्धियाँ वास्तविक हैं और इन्हें नकारना वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नहीं होगा।किन्तु लोकतंत्र केवल उपलब्धियों से नहीं चलता। लोकतंत्र का मूल्यांकन इस आधार पर भी होता है कि सत्ता आलोचना को कितना स्थान देती है,संस्थाएँ कितनी स्वतंत्र हैं,नागरिक कितने निभय हैं और विपक्ष को कितना सम्मान प्राप्त है।यहाँ से वर्तमान राजनीतिक बहस आरम्भ होती है। विपक्षी दल और अनेक राजनीतिक विश्लेषक आरोप लगाते हैं कि देश में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ है।प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर समय-समय पर प्रश्न उठते रहे हैं।विपक्ष का आरोप है कि इन एजेंसियों की सक्रियता कई बार राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध अधिक दिखाई देती है।सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है और कहती है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को राजनीतिक चरम से नहीं देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में सच्चाई का निर्णय अदालतें और कानून करते हैं,

लेकिन वह भी उतना ही सत्य है कि संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूँजी होता है।इसी प्रकार चुनाव आयोग को लेकर भी समय-समय पर बहस होती रही है।भारत का चुनाव आयोग विश्व की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है और उसकी निष्पक्षता लोकतंत्र की आधारशिला है।यदि चुनावी संस्थाओं को लेकर आशंकाएँ व्यक्त की जाती हैं तो उनका उत्तर केवल राजनीतिक बयान नहीं,बल्कि अधिक पारदर्शिता और जनविश्वास से दिया जाना चाहिए।लोकतंत्र की अमरली शक्ति केवल चुनाव कराने में नहीं, बल्कि चुनावों पर जनता के भरोसे में निहित होती है।आज देश का युवा एक अलग प्रकार के संकट से जूझ रहा है।करोड़ों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों लगा देते हैं,लेकिन तैयार भी नहीं हो पाते और विपक्ष को चोट पहुँचाती हैं।बेरोजगारी का प्रमुख मुद्दा है। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के बीच संतुलन की चुनौती अभी भी बनी हुई है।शिक्षा का विस्तार हुआ है,लेकिन गुणवत्तापूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर किसी भी सरकार को देना ही होगा।राजनीति का एक और चिंताजनक पक्ष दल-बदल की बढ़ती संस्कृति है।चुनाव के समय एक विचारधारा और दल के नाम पर वोट माँगना और बाद में राजनीतिक लाभ के लिए पाला बदल लेना लोकतांत्रिक नैतिकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश,कर्नाटक और अन्य राज्यों की राजनीतिक घटनाओं ने यह बहस तेज की है , क्या जनादेश जनता का रहता है या राजनीतिक प्रबंधन का साधन बन जाता है?दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि लगभग सभी दल सत्ता में रहते हुए दल-बदल का स्वागत करते हैं और विपक्ष में रहते हुए उसका विरोध करते हैं।यही भारतीय राजनीति दलो का वह चाल,चेहरा और चरित्र है जिसे जनता अब समझने लगी है।लोकतंत्र में समस्या केवल सरकार की नहीं होती,विपक्ष की भी होती है।यदि सत्ता आलोचना से असहज होती है तो विपक्ष भी कई बार रचनात्मक राजनीति के बजाय केवल विरोध

की राजनीति में उलझ जाता है।लोकतंत्र दोनों पक्षों की जिम्मेदारी से चलता है।सत्ता को जवाबदेह होना पड़ता है और विपक्ष को विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करना पड़ता है।धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे भारतीय राजनीति का हिस्सा रहे हैं।राम मंदिर का निर्माण करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय था और उसका ऐतिहासिक महत्व भी है।लोकतंत्र में आस्था के साथ जवाबदेही भी आवश्यक होती है।किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक परियोजना के संबंध में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए।इसी प्रकार हिन्दू-मुस्लिम ध्ववीकरण की राजनीति अल्पकालिक चुनावी लाभ दे सकती है,लेकिन दीर्घकाल के सामाजिक विश्वास और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। भारत की वास्तविक चुनौतियाँ रोजगार,शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि, पर्यावरण,सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता हैं।यदि राजनीतिक विमर्श इन मूल प्रश्नों से भटकर केवल भावनात्मक मुद्दों तक सीमित हो जाए तो लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है।चुनावी मीडिया के इस युग ने लोकतंत्र को नए अवसर और नई चुनौतियाँ दोनों दी हैं।आज नागरिकों के पास अपनी बात कहने के पहले से कहीं अधिक अवसर हैं। सरकार को आलोचना भी खुलकर हो रही है और समर्थन भी।इसके साथ ही फेक न्यूज,ट्रोल संस्कृति, दुष्प्रचार और वैचारिक कट्टरता जैसी समस्याएँ भी बढ़ी हैं।लोकतंत्र को केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं,बल्कि जिम्मेदारअभिव्यक्ति की भी आवश्यकता होती है।2024 के लोकसभा चुनाव ने भी भारतीय लोकतंत्र को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया।जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को तीसरा कार्यकाल दिया, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया कि लोकतंत्र में जनादेश समर्थन और संतुलन दोनों का संदेश देता है।यह परिणाम बताता है कि भारतीय मतदाता न किसी दल का स्थायी समर्थक है और न स्थायी विरोधी।वह समय-समय पर सरकारों को अवसर भी देता है और चेतावनी भी।यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुंदरता है।आज की सरकार के लिए इतिहास का संदेश स्पष्ट है। इन्दिरा गांधी का राजनीतिक कद बहुत बड़ा था, लेकिन जनता ने उन्हें भी सत्ता से

बाहर कर दिया था।इसलिए किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि लोकप्रियता स्थायी है या चुनौती सफलता अंतिम सत्य है। लोकतंत्र में जनसमर्थन निरंतर अर्जित करना पड़ता है।केवल अतीत की गलतियों को याद दिलाकर वर्तमान की चुनौतियों से बचा नहीं जा सकता।यदि बेरोजगारी,शिक्षा,सामाजिक सद्भाव,संस्थागत विश्वसनीयता और पारदर्शिता जैसे प्रश्न उठ रहे हैं तो उनका उत्तर इतिहास नहीं,वर्तमान नीतियाँ और परिणामों से देना होगा।साथ ही विपक्ष को भी यह समझना होगा कि हर राजनीतिक मतभेद को आपातकाल बताना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है।जनता केवल आलोचना नहीं,विकल्प भी चाहती है।लोकतंत्र भय और आरोपों से नहीं,बल्कि विश्वास और विकल्पों से मजबूत होता है।औं।भीराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो,यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वह अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगा।यह चेतावनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।जितनी संविधान निर्माण के समय थी।भारत का संविधान किसी दल,नेता या सरकार का दस्तावेज नहीं है।यह देश के नागरिकों का लोकतांत्रिक संकल्प है।सरकारें आती हैं,सरकारें जाती हैं, दल बनते हैं,दल टूटते हैं, नारे बोलते हैं,राजनीतिक समीकरण बदलते हैं,लेकिन संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना स्थायी रहती है।इतिहास हमें भयभीत करने के लिए नहीं,बल्कि सावधान करने के लिए होता है। 1975 का आपातकाल हमें यह सिखाता है कि लोकतंत्र कभी भी स्वतः सुरक्षित नहीं रहता।उसे निरंतर संरक्षित करना पड़ता है। वहीं वर्तमान समय हमें यह भी सिखाता है कि लोकतंत्र की मजबूती केवल अतीत की गलतियों को निगाने से नहीं,बल्कि वर्तमान की चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करने से आती है।भारत की लोकतांत्रिक यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि यहाँ सरकारें बनती हैं,बल्कि यह है कि यहाँ जनता सरकारों का मूल्यांकन करने,उनसे प्रश्न पूछने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बदलने का अधिकार रखती है।यही लोकतंत्र की आत्मा है,यही संविधान की शक्ति है।

उज्बेकिस्तानके खिलाफ जीत के बाद बोले रोनाल्डो-

हुआस्टन, एजेंसी। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के बाद ‘वी आर बैक’, यानी हम वापस आ गए कहा। रोनाल्डो ने फीफा विश्व कप के इस मैच में दमदार प्रदर्शन किया और दो गोल किए जिससे पुर्तगाल ने ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से करारी मात दी। इस जीत के साथ ही पुर्तगाल ने नॉकआउट के लिए दावा मजबूत कर लिया है।

मैच में चमके रोनाल्डो

रोनाल्डो पिछले मैच में गोल नहीं कर सके थे, जिसका दबाव उन पर दिख रहा था। रोनाल्डो ने इस मैच में शुरुआत से ही आक्रामक रख अपनाया। उन्होंने पहले छठे मिनट में गोल किया और फिर पहला हाफ खत्म होने से 39वें मिनट में दूसरा गोल दागा। रोनाल्डो इन दो गोल की मदद से पुर्तगाल के लिए विश्व कप में

पुर्तगाल ने नॉकआउट की ओर बढ़ाए कदम

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो गोल की मदद से पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। पुर्तगाल ने पिछले मैच में ड्रा खेला था, लेकिन टीम इस मैच में बड़ी जीत दर्ज करने में सफल रही। टीम



के लिए रोनाल्डो ने दमदार प्रदर्शन किया। रोनाल्डो ने मैच के बाद ‘आई एम बैक’, यानी मैं वापस आ गया हूं कहा। रोनाल्डो पिछले मैच में गोल नहीं कर सके थे, लेकिन इस मैच में दमदार प्रदर्शन करने में सफल रहे। उज्बेकिस्तान की टीम का सफर ग्रुप चरण में ही थम गया।

पुर्तगाल के लिए रोनाल्डो के अलावा नूनो मंडेस और राफेल लियाओ ने एक-एक गोल किए। वहीं, उज्बेकिस्तान के नेमातोव ने आत्मघाती गोल किया।इसके साथ ही पुर्तगाल ग्रुप के चार अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है और उसने नॉकआउट के लिए दावा मजबूत कर लिया है। पुर्तगाल के दो मैचों में एक जीत और एक ड्रा से चार अंक हो गए हैं। दूसरे स्थान पर कोलंबिया है जो एक मैच में एक जीत के साथ तीन अंक लेकर दूसरे नंबर पर है। कॉंगो डीआर एक अंक के साथ तीसरे और उज्बेकिस्तान दो मैच में दो हार के साथ चौथे स्थान पर है।

उज्बेक खिलाड़ी ने किया आत्मघाती गोल

दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान के अब्दुखोदिर खुसानोव ने आत्मघाती गोल किया जिससे पुर्तगाल 4-0 की बढ़त बनाने में सफल रहा। दरअसल, पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडिस ने कॉर्नर पर किक मारा और गोल पोस्ट के पास खड़े खुसानोव के कंधे से लगते ही गेंद गोल पोस्ट को पार कर गई। इसके बाद पुर्तगाल ने पांचवां गोल कर उज्बेकिस्तान के खिलाफ बढ़त को बेहद मजबूत कर लिया। पुर्तगाल के लिए पांचवां गोल राफेल लियाओ ने 87वें मिनट में किया। उज्बेकिस्तान की टीम अंत तक मैच में एक भी गोल नहीं कर सकी।

वी आर बैक...

सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इतना ही नहीं रोनाल्डो छह अलग-अलग विश्व कप में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।

जीत के बाद गदगद हुए रोनाल्डो

उज्बेकिस्तान के खिलाफ जैसे ही पुर्तगाल ने जीत दर्ज की, रोनाल्डो खुशी से झूम उठे। रोनाल्डो दर्शक दीर्घा के पास जाकर कुछ बोलते सुनाई दिए। उन्होंने बाद में इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल लिखा, ‘वी आर बैक’। फोटो में वह अपनी सिग्नेचर स्टाइल में खड़े नजर आए। रोनाल्डो और पुर्तगाल के लिए यह जीत काफी अहम है क्योंकि टीम के लिए फीफा विश्व कप की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने डीआर कांगो के खिलाफ 1-1 से ड्रा खेला था, लेकिन उज्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल पूरे दम में नजर आई और एकतरफा अंदाज में मैच जीता।



लियोनल मेसी: 39 के हुए फुटबॉल के जादूगर!

संन्यास लिया...वापसी की और फिर दुनिया जीत ली

न्यूयॉर्क, एजेंसी। फुटबॉल की दुनिया में महानतम खिलाड़ी को लेकर बहस कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब आंकड़ों, उपलब्धियों और मैदान पर जादू की बात आती है तो लियोनल मेसी का नाम सबसे आगे दिखाई देता है। 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में जन्मे मेसी आज 39 साल के हो गए हैं। उनका यह जन्मदिन इसलिए भी खास है क्योंकि वह फीफा विश्व कप 2026 में शानदार फॉर्म में हैं। मेसी ने विश्वकप में ओवरऑल मिरोस्लाव क्लोज के सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड तोड़ा और फिलहाल पांच गोल के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष गोल स्कोरर बने हुए हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया एक बार फिर उस खिलाड़ी का जश्न मना रही है जिसने अपने करियर में लगभग हर सपना पूरा किया।

बीमारी से जंग, फिर दुनिया पर राज

आज जिस खिलाड़ी को दुनिया फुटबॉल का भगवान कहती है, उसका बचपन संघर्षों से भरा था। महज 11 साल की उम्र में मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नामक बीमारी हो गई थी। इस बीमारी के कारण उनका शारीरिक विकास रुक गया था और इलाज बेहद महंगा था।उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि लगातार इलाज का खर्च उठा सके। तभी स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। कहा जाता है कि मेसी का पहला अनुबंध एक नैपकिन पेपर पर लिखा गया था। वहीं नैपकिन आगे चलकर फुटबॉल इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल हो गईं।

बार्सिलोना में शुरु हुआ स्वर्णिम युग

बार्सिलोना पहुंचने के बाद मेसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले डेढ़ दशक तक उन्होंने क्लब फुटबॉल पर लगभग एकछत्र राज किया। बार्सिलोना के लिए उन्होंने 778 मैचों में 672 गोल किए और क्लब के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बने। उनके नेतृत्व में बार्सिलोना ने 10 ला लीगा, 4 यूईएफए चैंपियंस लीग, 7 कोपा डेल रे और कई अन्य ट्रॉफियां जीतीं। साल 2012 उन्होंने एक केंलेंडर वर्ष में 91 गोल दागकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।



आलोचनाओं से टूटे, संन्यास लेकर दुनिया को चौंकाया

मेसी के करियर का सबसे भावुक पल 2016 में आया। अर्जेंटीना लगातार बड़े टूर्नामेंटों के फाइनल हार रहा था और कोपा अमेरिका फाइनल में चिली के खिलाफ पेनाल्टी चूकने के बाद मेसी बुरी तरह टूट गए। मैच के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। यह खबर सुनकर अर्जेंटीना ही नहीं, पूरी दुनिया के फुटबॉल प्रशंसक स्तब्ध रह गए। आलोचकों का मानना था कि मेसी दबाव में बड़े खिताब नहीं जिता सकते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जेंटीना की जनता, पूर्व खिलाड़ियों और देशभर से उठी भावनात्मक अपीलों के बाद मेसी ने अपना फैसला बदला और राष्ट्रीय टीम में लौट आए। इसके बाद उन्होंने वह कर दिखाया जिसका इंतजार करोड़ों अर्जेंटीनी वर्षों से कर रहे थे। 2021 में अर्जेंटीना को कोपा अमेरिका जितकर उन्होंने 28 साल का खिताबी सूखा खत्म किया। इसके बाद 2022 में फाइनलिस्टा और फिर विश्व कप जीतकर उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी कमी भी पूरी कर ली। उनकी वापसी फुटबॉल इतिहास की सबसे सफल वापसी में गिनी जाती है।

व्यापार

तमिलनाडु आ सकता है बजाज का नया ईवी प्लांट, पैदा होंगी बंपर नौकरियां

नई दिल्ली, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार के साथ सॉलिसी और इंसेंटिव से जुड़े विवादों के चलते दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी बजाज ऑटो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैनुफैक्चरिंग प्लांट के अगले विस्तार को राज्य से बाहर ले जाने की तैयारी में है। सीएनबीसी-टीवी18 के मुताबिक इस रेस में तमिलनाडु सबसे आगे

चल रहा है। अगर यह हक कंपनी तमिलनाडु में आती है तो यह सी. जोसेफ विजय (थलपति विजय) सरकार के लिए बड़ा मौका होगा। इससे प्रदेश में कई नौकरियां पैदा होंगी। इससे पहले भी कई कंपनियों ने थलापति विजय सरकार के साथ प्रदेश में बड़े निवेश और रोजगार के लिए समझौते किए हैं। यह पूरा मामला महाराष्ट्र सरकार की ईवी पॉलिसी और पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता (रिजेंबर्समेंट) में हो रही देरी से जुड़ा है। महाराष्ट्र सरकार के सामने बार-बार अपनी बात रखने के बावजूद जब इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, तो बजाज ऑटो ने अपने अगले फेज के ईवी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए अन्य राज्यों का रुख करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी 2021 के नियमों के मुताबिक कंपनियों को गाड़ी की बिक्री के समय ही सरकारी सॉलिसी का फायदा सीधे ग्राहकों को देना था। बाद में सरकार से उसका रिजेंबर्समेंट लेना था।



रांची में पुष्पांजलि डेवलपर का 50 करोड़ का बड़ा निवेश, बरियातू में ‘पुष्पांजलि हिल व्यू रेजिडेंसी’ का भव्य भूमि पूजन संपन्न

रांची। झारखंड की राजधानी रांची के रियल एस्टेट क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी पुष्पांजलि डेवलपर द्वारा बरियातू क्षेत्र में अपने महत्वाकांक्षी आवासीय प्रोजेक्ट ‘पुष्पांजलि हिल व्यू रेजिडेंसी’ का भूमि पूजन समारोह 24 जून 2026 को विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर कंपनी के चेयरपर्सन गोविंद आनंद ने कहा कि पुष्पांजलि हिल व्यू रेजिडेंसी आधुनिक वास्तुकला, उत्कृष्ट निर्माण गुणवत्ता और विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, जो रांची के आवासीय क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य केवल भवन निर्माण करना नहीं, बल्कि लोगों के सपनों का घर तैयार करना है। श्री आनंद ने जानकारी दी कि पुष्पांजलि डेवलपर रांची में अपने विस्तार की योजना के तहत जल्द ही दो और बड़े



प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। इनमें एक अत्याधुनिक कमर्शियल आईटी स्पेस (Commercial IT Space) तथा दूसरा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शामिल होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा तथा निर्धारित समय से पूर्व उन्हें पूर्ण

■ **24 जून 2026 को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ भूमि पूजन, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य; रांची में दो और बड़े प्रोजेक्ट लाने की तैयारी।**



कर ग्राहकों को सौंपा जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी रांची के

इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रियल एस्टेट विकास में लगभग 50 करोड़ रुपये का निवेश



करेगी। यह निवेश न केवल शहर के शहरी विकास को गति देगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन करेगा। भूमि पूजन समारोह में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित आनंद, डायरेक्टर विल्लु किशोर बैठा, तंज्योत सिंह तथा शिवजी कुमार सहित कंपनी के अन्य पदाधिकारी, व्यवसायी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इस परियोजना को रांची के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी

पहल बताते हुए इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। रियल एस्टेट क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि ‘पुष्पांजलि हिल व्यू रेजिडेंसी’ परियोजना रांची के आवासीय बाजार को नई दिशा देगी और शहर के तेजी से हो रहे शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गुणवत्तापूर्ण निर्माण, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्यशैली के साथ पुष्पांजलि डेवलपर रांची में अपनी एक मजबूत पहचान बनाने की ओर अग्रसर है।

एक्सपर्ट्स की राय: मौका भी, सावधानी भी

नवरत्न कंपनी में सरकार बेच रही हिस्सेदारी, शेयर 5% टूटा; निवेशकों के लिए मौका या रिस्क

नईदिल्ली, एजेंसी। सरकार की ओर से हिस्सेदारी बिक्री की घोषणा के बाद रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन के शेयर बुधवार को दबाव में रहे। नवरत्न कंपनी इन्फ्रस्ट्रक्चर शेयर 5% से ज्यादा टूटकर 93.59 रुपये तक पहुंच गया। मंगलवार को शेयर 98.67 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि बुधवार को 94 रुपये पर खुला।

केंद्र सरकार के जरिए अपनी 1% हिस्सेदारी बेच रही है, जो करीब 13.06 करोड़ शेयरों के बराबर है। इसके अलावा सरकार ने 1% अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का विकल्प (ग्रीनशू ऑफ़ेशन) भी रखा है। यानी मांग अच्छी रहने पर कुल 2% हिस्सेदारी बाजार में आ सकती है। स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि फ्लोर प्राइस 91 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह शेयर के पिछले बंद भाव से करीब 7.5% कम है। नॉन-रिटेल निवेशकों के लिए बुधवार को खुला, जबकि रिटेल निवेशक गुरुवार को इसमें हिस्सा ले सकेंगे।



की उपलब्धता (फ्री फ्लोट) बढ़ेगी, जिससे स्टॉक की लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है। बिजनेस हेड हर्षल दसानी के मुताबिक का केवल डिस्काउंट पर शेयर खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि यह निवेशकों की रेलवे पीएचयू शेयरों में आगे की संभावनाओं पर राय का भी परीक्षण है। उनका कहना है कि रेलवे कैपेक्स फाइनेंसिंग के केंद्र में है और

इसका बिजनेस मॉडल सरकारी समर्थन से जुड़ा हुआ है, जिससे बैलेंस शीट का जोखिम कम रहता है। हालांकि, रेलवे शेयरों में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी तेजी आ चुकी है, इसलिए वैल्यूएशन अब पहले जितना आकर्षक नहीं माना जा सकता।

कांतिलाल छगनलाल सिक्कोरिटीज के महेश ओझा का मानना है कि 91 रुपये का फ्लोर प्राइस मौजूदा बाजार कीमत के मुकाबले आकर्षक दिखता है, लेकिन रिटेल निवेशकों को ह्रस्त्र में भाग लेने से पहले यह देखना चाहिए कि संस्थागत निवेशकों की मांग कैसी रहती है और अंतिम कट-ऑफ प्राइस क्या निकलती है।

ओएफएस भारतीय रेलवे की प्रमुख फाइनेंसिंग कंपनी है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार का यह कदम उसके विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा है। इससे पहले इस साल कोल इंडिया, एनएचपीसी, एनएलसी इंडिया, स्टेल्स बैंक ऑफ इंडिया और जीआईसी में भी ह्रस्त्र लाया जा चुका है।

8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा फैसला ! कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, सरकार ने दी राहत

नईदिल्ली, एजेंसी। 8वें वेतन आयोग को लेकर देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी बड़ी उमीदें लगाए बैठे हैं। खासकर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेकर कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हालांकि, अभी सभी कर्मचारियों के लिए बहाल नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने एक खास कैटेगिरी के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दरअसल, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 22 जून 2026 को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, ऐसे कर्मचारी जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली है और जिनका आवेदन 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले जमा हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल किया जा सकता है, भले ही उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने नई पेंशन प्रणाली लागू की थी। इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों

को का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन कई मामलों में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन



2003 से पहले जमा हुए थे, जबकि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के कारण नियुक्तियां बाद में हुईं। ऐसे कर्मचारियों को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था कि उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब नियुक्ति की तारीख के बजाय आवेदन की तारीख को आधार माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी परिवार ने 31 दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया था और वह उस समय पात्र था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। यह फैसला हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत

लेकर आया है। अनुकंपा नियुक्ति उन परिवारों को दी जाती है जिनके परिवार का कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान निधन हो जाए या चिकित्सीय कारणों से सेवानिवृत्त हो जाए। ऐसे परिवारों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए सरकार यह सुविधा देती है। इस फैसले का स्वागत ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन सहित कई कर्मचारी संगठनों ने किया है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इसे कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जैसा बताया है। हालांकि उन्होंने सरकार से सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन देने की मांग भी दोहराई है। इस बीच 8वें वेतन आयोग की बैठकों में भी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कर्मचारी संगठन लगातार की बहाली, बेहतर पेंशन सुर्खा और रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार का यह फैसला केवल एक सीमित वर्ग के कर्मचारियों के लिए है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद जकी हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया। संपादक :- सैयद जकी हैदर- हेड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928 जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कर्नोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM	
किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।	
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।	
क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)	

